सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 218, नई दिल्ली । गुरुवार, 17 अक्टूबर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है।

03 डॉ. के लक्ष्मण को संगठनात्मक चुनाव के लिए राष्ट्रीय चुनाव...
06 भारतीय छात्र पाठ्यपुस्तकों की तुलना में यूट्यूब को क्यों पसंद करते हैं?
08 सामाजिक बदलाव के लिएसेवकआर्मी डॉट कॉम शुरू

हरियाणा परिवहन आयुक्त द्वारा बस एंड कार ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन आफ इंडिया की शिकायत पर जारी किए आदेश, जाने

संजय बाटला

नई दिल्ली। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दस्तावेजों का जारी होना। उपरोक्त विषय पर संदर्भ विभाग के संज्ञान में आया है कि पंजीकरण/परमिट देने वाले अधिकारी प्रमाण-पत्रों को सत्यापित करने के लिए पुराने/समाप्त हो चुके परमिटों की भौतिक प्रतियाँ प्रस्तुत करने पर जोर दे रहे हैं, जिससे आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में देरी हो रही है। ऑनलाइन मोड में जारी किए गए परमिटों का पूरा विवरण पहले से ही वाहन पोर्टल पर उपलब्ध है और साथ ही केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 172 में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के निर्माण/जारी करने और प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, ऐसे दस्तावेजों को उक्त पोर्टल से जारी दस्तावेजों का विवरण प्राप्त करके सत्यापित किया जा सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.09.2023 को RT-11036/03/2023-MVL संख्या के माध्यम से एक परामर्श भी जारी किया गया है, जिसमें अधिकारियों से पुराने/समाप्त हो चुके परमिटों की भौतिक प्रतियाँ जमा नहीं करने के लिए आग्रह किया गया है। इसकी एक प्रति संलग्न है।

इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि पुराने/समाप्त हो चुके परमिटों की भौतिक प्रतियां प्राप्त करने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए और किसी भी आवेदक को ऐसे परमिटों के अनुदान/नवीनीकरण के समय पुराने/समाप्त हो चुके परमिटों (जिनकी वैधता समाप्त हो गई है/समाप्त हो रही है) की भौतिक प्रतियां जमा करने के लिए जोर नहीं दिया जाए। उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। कन्फेडरेशन द्वारा भेजे गए पत्र और विभाग द्वारा जारी निर्देश की मूल एवम्-हिन्दी में परिवर्तित कापी आप सभी की जानकारी के लिए सलग्न

Regn. No. S/2125/Distt.South/2016

BUS AND CAR OPERATORS CONFEDERATION OF INDIA

Regd. Office : Flat No. 110, 1st Floor, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi - 110 001
General Secretary Office : #148, Perambur Barracks Road, Purasawalkam, Chennai - 600 007
Contact : 0 98903 10331 / 0 98400 41999 | E-mail : ho@boci.org.in

BOCI/CMVR/131/24 — 6.10.2024

Mr Yashendra Singh IAS
Transport Commissioner,
Transport Department,
Govt of Haryana
Chandigarh , Haryana 160017

Respected Sir,

The Bus & Car Operators Confederation of India (BOCI) are a Pan India Apex Body representing over 80% of India's Bus Operations including the Private & Public Sector. Our members operate the fleets of over 15 lakh buses and 11 lakh Tourist cabs in eight important passenger Transport segments viz; Intercity, Intercity, School Bus, Employee Transport, Tour Operators, Tourist

We like to bring your kind notice that at the time of renewal of permits, the Transport Department, Gurugram and Faridabad insists on submitting the copy of the expired permits. It is pertinent to mention that the permits are issued in paper form and are sometimes not possible to keep safe after five years from the date of its issue. If the Transport Department wishes to verify the details/ correctness of the permit at the time of renewal, they can verify the details through VAHAN which is in lieu with the rules framed under the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

We would like to refer to the Ministry of Road Transport & Highways letter No. RT-11036/03/2023-MVL dated 18th September, 2023 wherein the Ministry has also advised all the States/UTs not to insist on physical copies of old/expired permits (whose validity has expired or expiring) in case their details can be verified electronically through portal (VAHAN). Copy enclosed for ready Reference.

In view of the above, we request your good self to direct all the concerned departments relating to grant/ renewal of permit not to insist on submitting **physical copies of old/expired permits at the time of renewal of permits if the details of the same can be verified electronically through the portal.**

Yours faithfully,
Thanking You,
Yours Faithfully ,
Bus & Car Operators Confederation of India

Prasanna Patwardhan — President
Gurmit Singh Taneja — Chairman (CMVR Committee) — 9810048840

Chairman: Jagdev Singh Khalsa, MD, Khalsa Travels, Jodhpur
President: Prasanna Patwardhan, CMD, Prasanna Purple, Pune
General Secretary: A. Afzal, CMD, Parveen Travels, Chennai
Treasurer : Harsh Kotak, MD, Modern Transport, Mumbai
Joint Secretary : Babu Panicker, Panicker's Travel (India) Pvt. Ltd
Additional Secretary : D.R. Dharmaraj, MD, Dharmaraj Transports, Trichy
Joint Treasurer: D. Maran, MD, Sri Bhagyalakshmi Travels, Chennai

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणासरकार TRANSPORT COMMISSIONER, HARYANA, CHANDIGARH परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़

राज्य के सभी डीटीओ-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण।

मेमो क्रमांक 52413-34 /एटी-2/एसटी-III दिनांक 15/10/24

विषयः मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दस्तावेजों का जारी होना।

उपरोक्त विषय पर संदर्भ.

विभाग के संज्ञान में आया है कि पंजीकरण/परमिट देने वाले अधिकारी प्रमाण-पत्रों को सत्यापित करने के लिए पुराने/समाप्त हो चुके परमिटों की भौतिक प्रतियाँ प्रस्तुत करने पर जोर दे रहे हैं, जिससे आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में देरी हो रही है। ऑनलाइन मोड में जारी किए गए परमिटों का पूरा विवरण पहले से ही वाहन पोर्टल पर उपलब्ध है और साथ ही केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 172 में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के निर्माण/जारी करने और प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, ऐसे दस्तावेजों को उक्त पोर्टल से जारी दस्तावेजों का विवरण प्राप्त करके सत्यापित किया जा सकता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.09.2023 को RT-11036/03/2023-MVL संख्या के माध्यम से एक परामर्श भी जारी किया गया है, जिसमें अधिकारियों से पुराने/समाप्त हो चुके परमिटों की भौतिक प्रतियाँ जमा करने के लिए आग्रह किया गया है। इसकी एक प्रति संलग्न है।

इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि पुराने/समाप्त हो चुके परमिटों की भौतिक प्रतियां प्राप्त करने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा और किसी भी आवेदक को ऐसे परमिटों के अनुदान/नवीनीकरण के समय पुराने/समाप्त हो चुके परमिटों (जिनकी वैधता समाप्त हो गई है/समाप्त हो रही है) की भौतिक प्रतियां जमा करने के लिए जोर नहीं दिया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(बलजिंदर सिंह) अधीक्षक, परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़। 2

दिनांकः 15/10/24

अंतिम सं. 52435-37/एटी-2/एसटी-III

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जा रही हैः-

1. अवर सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमवीएल अनुभाग), परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके ज्ञापन संख्या आरटी-11036/03/2023-एमवीएल दिनांक 18.09.2023 के संदर्भ में।

2. निजी सचिव/निजी सचिव (टी) को प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, हरियाणा के सूचनार्थ।

टेलीफ़ोनः 91(0172)-2784359

कार्यालयः 30 खांडविल्डिंग, दुसरातल, सेक्टर 17बी, चंडीगढ़-160017 (भारत)

कार्यालयः 30 बेज़ बिल्डिंग, द्वितीय तल, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017 (भारत), 2701290, 2700541

फैक्सः 91(0172)2700514

ई-मेल : stcharyana@hry.nic.in

वेबसाइटःharyanatranspor

GOVERNMENT OF HARYANA/ हरियाणासरकार
TRANSPORT COMMISSIONER, HARYANA, CHANDIGARH
परिवहनआयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़

To
All DTOs-cum-Secretaries,
Regional Transport Authorities,
In the State.

Memo No. 52413-34 /AT-2/ST-III Dated 15/10/24

Subject:- Issue of documents under Motor Vehicles Act, 1988.

Reference on the subject cited above.

It has come to the notice of the Department that the Registering/Permit granting authorities have been insisting to submit physical copies of old/expired permits to verify the credentials which cause delay in providing the required services. All the details of permits issued in online mode is already available on the Vahan portal as well as creation/issue and grant of electronic documents has also been provided in rule 172 of Central Motor Vehicles Rules, 1989. Further, such documents can be verified by fetching the details of issue documents from the said portal.

An advisory has also been issued by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India vide no. RT-11036/03/2023-MVL dated 18.09.2023 regarding insisting of authorities for deposit of physical copies of old/expired permits. A copy of the same is enclosed herewith.

It is therefore, directed that the practice of getting physical copies of old/expired permits shall be done away with and no applicant be insisted to deposit physical copies of old/expired permits (whose validity is expired/expiring) at the time of grant/renewal of such permits.

The above directions should be followed in letter & spirit.

Encl: As above

(Baljinder Singh)
Superintendent
O/o Transport Commissioner,
Haryana, Chandigarh.

Endst No. 52435-37 /AT-2/ST-III Dated : 15/10/24

A copy of the above is forwarded to:-

1. Under Secretary to Government of India, Ministry of Road Transport and Highways (MVL Section), Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110001 w.r.t. his memo no. RT-11036/03/2023-MVL dated 18.09.2023.
2. PS/PS(T) for kind information of Principal Secretary, Transport Department, Haryana.

Office: 30 Bays Building, 2nd Floor, Sector 17-B, Chandigarh - 160017 (India)
Telephone: 91(0172)-2784359, 2701290, 2700541 Fax: 91(0172)2700514 e-mail:stcharyana@hry.nic.in website:haryanatransport.gov.in
कार्यालय: 30 खण्डविल्डिंग, दूसरातल, सेक्टर17 बी, चंडीगढ़-160017 (भारत) AT-2

क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष परिवहन आयुक्त एडमिन द्वारा क्यों लगाए गए ग़ैर तकनीकी अधिकारी ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। क्या परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में जितने भी कार्य किए जाते है वह गैर तकनीकी है ? किस आधार नियम क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष परिवहन आयुक्त एडमिन शाखा द्वारा डीटीओ की पदो पर जानबूझकर गिर तकनीकी अधिकारी को नियुक्त किया। नियमानुसार क्षेत्रीय कार्यालयों में

1. ई रिक्शा की फिटनेस जो तकनीकी अधिकारी का कार्य है।
2. वाहनों की एनओसी जारी करना जो तकनीकी अधिकारी का कार्य है।
3. किसी भा वाहन चालक को लाइसेंस जाती करना जो तकनीकी अधिकारी को कार्य है।
4. वाहन का पंजीकरण जो तकनीकी अधिकारी का कार्य है।
5. वाहनों के दस्तावेजों की जांच जो एक तकनीकी अधिकारी का कार्य है।
6. वाहनो में फ्यूल मोड का चेज के आदेश और उस की जांच हेतु फ्यूल मोड चेंज करने की अप्रूवल जो एक तकनीकी अधिकारी का कार्य है।

परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी कार्य तकनीकी पर क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारी ग़ैर तकनीकी,

सीएमवीआर, सर्विस बुक, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश, माननीय कैट के दिशा निर्देश, लॉ विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार जो की सिर्फ तकनीकी अधिकारी ही कर सकते है उन पदो पर किस आधार का अंतर्गत विशेष परिवहन आयुक्त एडमिन द्वारा गैर तकनीकी अधिकारी नियुक्त किए बड़ा सवाल ?

क्या दिल्ली की जनता की जान माल का असुरक्षित करना की उद्देश्यों से या फिर अन्य उद्देश्य से एक प्रशासनिक अधिकारी नियमो को दरकिनार करके गैर तकनीकी अधिकारी को नियुक्त कर रहा है। क्या राजस्व में इजाफा करने के उद्देश्य से तकनीकी अधिकारी की जगह पर गैर तकनीकी अधिकारी जिन्हें राजस्व इजाफा करवाने की ज़्यादा जानकारी है को नियुक्ति दी गई है।

सवाल तो उठता है क्योंकि जनता की सुरक्षा का मामला है।

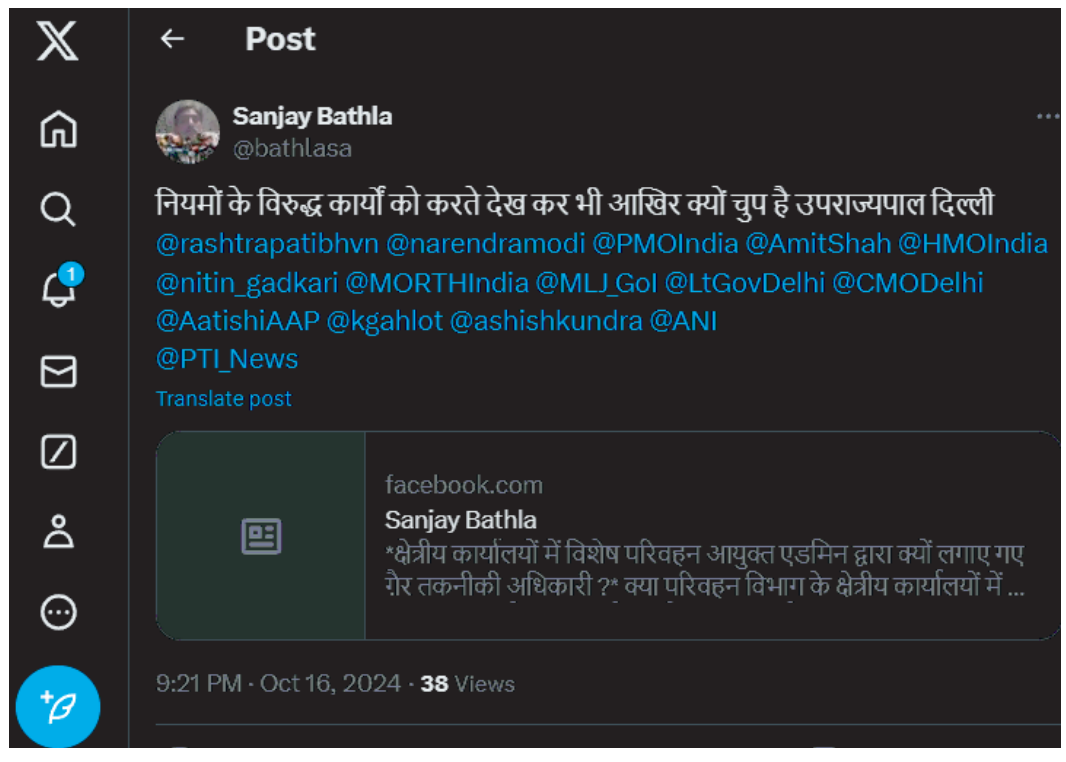

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली में काटे गए 15 लाख के ताबड़तोड़ चालान मचा हड़कंप; भूलकर भी न करें ये गलतियां

परिवहन विशेष न्यूज

राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों के ताबड़तोड़ चालान काटे गए। बताया गया कि वायु प्रदूषण को लेकर एनडीएमसी ने 15 लाख रुपये के 30 चालान किए हैं। ऐसे में अगर आपने भी यह गलती की तो आपका भी चालान काटा जा सकता है। पढ़िए आखिर राजधानी में लोगों को किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एनडीएमसी द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं। जिसमें निरीक्षण, पर्यवेक्षण और कार्रवाई की निगरानी के लिए गठित विभिन्न टीमों द्वारा उल्लंघनकर्ताओं का चालान भी किया जा रहा है।

वहीं, दिल्ली में ताबड़तोड़ चालान काटे जाने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में अगर कोई भी निमयों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी।

एनडीएमसी के निदेशक (ईबीआर) के नियंत्रण में अधिकारियों की एक टीम ने निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया है। धूल प्रदूषण के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 15 लाख रुपये के 30 चालान किए।

पढ़ें मुख्य बातें-

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों पर किए गए चालान

दिल्ली में 15 लाख रुपये के 30 चालान किए गए हैं

एमआरएस द्वारा प्रतिदिन औसतन 227 किमी की सफाई की जाती है।

एनडीएमसी ने 5000 लीटर से 10 हजार लीटर की क्षमता वाले 20 वाटर टैंकर तैनात किए हैं।

एनडीएमसी ने बिना धूल उड़ाए सफाई के लिए जीपीएस ट्रैकिंग के साथ दो शिफ्टों में छह मैकेनिकल रोड स्वीपर (एमआरएस) तैनात किए हैं।

पालिका केंद्र में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र से उस पर निगरानी की जा रही है।

इसी तरह कूड़ा-कचरा, एकल उपयोग प्लास्टिक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्थान पर कचरे या सूखे पत्तों को जलाने के लिए 290 उल्लंघनकर्ताओं को 48,747 रुपये के चालान जारी किए।

वहीं, एनडीएमसी के एक अधिकारी के अनुसार एनडीएमसी ने बिना धूल उड़ाए सफाई के लिए जीपीएस ट्रैकिंग के साथ दो शिफ्टों में छह मैकेनिकल रोड स्वीपर (एमआरएस) तैनात किए हैं।

प्रतिदिन औसतन 227 किमी की जाती है सफाई

इन एमआरएस द्वारा प्रतिदिन औसतन 227 किमी की सफाई की जाती है। सभी एवेन्यू सड़कों की प्रतिदिन या वैकल्पिक दिनों पर यांत्रिक रूप से सफाई की जा रही है। पालिका केंद्र में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र से उस पर निगरानी की जा रही है।

इसी तरह नई दिल्ली क्षेत्र में हवा और पर्यावरण में धूल के कणों को कम करने के लिए एनडीएमसी की सड़कों पर आठ मोबाइल एंटी-स्मॉग गन चलाई जा रही हैं। साथ ही एक स्टैटिक एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल पंडित पंत मार्ग पर किया जा रहा है।

कचरा जलाने की जगहों का किया जा रहा निरीक्षण

एनडीएमसी ने 5000 लीटर से 10 हजार लीटर की क्षमता वाले 20 वाटर टैंकर तैनात किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की 14 टीमें दिन के समय सर्कल-वार तैनात की गई हैं, जो कचरा जलाने की जगहों का निरीक्षण कर रही है।

आईए जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व और शरद पूर्णिमा पर बनाए जाने वाली 'खीर' का महत्व-:

हमारी सनातन परंपरा में प्रत्येक त्योहार मनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है। फिर चाहे वह कारण ज्योतिष आधारित हो, धर्म पर आधारित हो या फिर वैज्ञानिक कारण, ऐसे ही शारदेय नवरात्र के बाद शरद पूर्णिमा मनाने का भी एक बेहद खास कारण है। शरद पूर्णिमा आश्विन माह की शुक्ल पक्ष के दिन हर वर्ष शरद पूर्णिमा के रूप में लोग मनाते हैं। इस बार यह शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 मनाया जाएगा।

* शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ होता है और शरद पूर्णिमा की रात निकलने वाले चांद की किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं। इसलिए इस दिन खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाती है और मान्यताओं के अनुसार इस खीर में चंद्रमा का अमृत उतरता है/

* ऐसा माना जाता है कि इस रात माता लक्ष्मी इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। इसलिए लोग इस दिन लक्ष्मी माता के भोग के लिए खीर भी बनाते हैं। साथ ही लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग विधि- विधान के साथ पूजा भी करते हैं/

* सनातन ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर श्रीकृष्ण ने नौ लाख गोपिकाओं के साथ कई सारे रूपों में महारास रचाया था इसलिए इस रात का विशेष महत्व होता है/

* आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा की रात पर महर्षी च्यवन को आरोग्य का पाठ और औषधि का ज्ञान अश्विनी कुमारों ने ही दिया था। इस कारण से अश्विनी कुमार आरोग्य के दाता हैं और पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत माना जाता है/

* शरद पूर्णिमा पर उत्तर भारत के ज्यादातर लोग अपनी छत पर खीर बनाकर इसलिए रखते हैं ताकि चंद्रमा की अमृत की बूंदें खीर में समा जाए। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद खीर खाने से समस्त रोग दूर होते हैं। अर्थात इस खीर में गिरे हुए अमृत के कारण आरोग्य प्राप्त होता है/

16 अक्टूबर, बुधवार की रात को खीर बनाकर चंद्रमा के प्रकाश में रखी जाएगी, उसके उपरांत अगले दिन माता लक्ष्मी जी व भगवान श्री हरि विष्णु जी के भोग लगाने के पश्चात प्रसाद को वितरित किया जाएगा।

धीरे-धीरे हड्डियों को कमजोर बना रही हैं आपकी 5 गलतियां, नहीं सुधरे तो जर्जर होकर गिर जाएगा ढांचा!

स्वस्थ जीवन हर कोई चाहता है लेकिन इसके लिए मजबूत हड्डियां (strong bones) होना बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि हमारी कुछ छोटी-छोटी आदतें धीरे-धीरे हमारी हड्डियों को कमजोर (weak bones) बनाने का काम करती हैं? आइए इस आर्टिकल में ऐसी 5 आदतों (Habits Silently Weakening Your Bones) के बारे में जानें जिन्हें छोड़कर आप हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।

नईदिल्ली। क्या आपको भी लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर (weak bones) हो रही हैं? यह सच है कि उम्र के साथ बोन डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप कुछ आसान बदलावों से अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन-सी 5 गलतियां (Habits Weakening Your Bones) आपकी हड्डियों को कमजोर बना रही हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं।

ज्यादा मीठा

ज्यादा मीठा खाने से न सिर्फ आपका वजन बढ़ता है बल्कि आपकी हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं। जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ता है। यह बढ़ा हुआ ब्लड शुगर कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसके अलावा, ज्यादा वजन हड्डियों पर एक्स्ट्रा दबाव डालता है जिससे हड्डियों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

ज्यादा नमक

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब खान-पान की आदतों ने हमारी हड्डियों को कमजोर बना दिया है। खासकर, नमक का अत्यधिक सेवन हड्डियों के लिए बेहद हानिकारक है। नमक में मौजूद सोडियम, कैल्शियम को शरीर से बाहर निकाल देता है जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए, ध्यान रखें कि आप अपनी डाइट में नमक को मात्रा को कम करके अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं।

ऑक्सलेट फूड्स

आपको चॉकलेट, केक, पेस्ट्री और कुकीज जैसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का लुत्फ उठाना बहुत पसंद होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें मौजूद ऑक्सलेट आपके हड्डियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं? ऑक्सलेट कैल्शियम के अवशोषण को रोककर आपकी हड्डियों को कमजोर बना सकते हैं, इसलिए मजबूत हड्डियां चाहते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें।

धूप न लेना

धूप सेकना सिर्फ टैनिंग के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी होता है? सूरज की किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी का उत्पादन करती हैं, जो कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रोजाना कुछ देर धूप में बैठना बहुत जरूरी है।

फ्राइड फूड्स

तला-भुना खाना खाने का शौक भी आपकी हड्डियों को कमजोर बनाता है। जी हां, फ्राई किए गए खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा अधिक होती है जो कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालता है। इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, स्वस्थ हड्डियों के लिए आपको अपनी डाइट से तले-भुने खाद्य पदार्थों को कम करना चाहिए।

5 मौके, जब लड़कियों से भी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं लड़के! वे नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ें यह खबर

आमतौर पर ये माना जाता है कि लड़कियां हर छोटी-छोटी बात पर घबरा जाती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार लड़के भी लड़कियों से ज्यादा नर्वस हो जाते हैं? इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे 5 मौकों (Nervous Situations) के बारे में बताएंगे जब लड़के लड़कियों से कहीं ज्यादा नर्वस महसूस करते हैं और इस बात को लड़कियों से छिपाने की भरपूर कोशिश भी करते हैं।

नई दिल्ली। क्या आपको लगता है कि सिर्फ लड़कियां ही ज्यादा नर्वस होती हैं? अगर हां, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। यहां हम आपको कुछ ऐसी सिचुएशन्स (What Makes A Boy Nervous) के बारे में बताएंगे जब लड़के लड़कियों से ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और इस बात को लड़कियों के सामने जाहिर भी नहीं होने देते हैं। अब इसके पीछे चाहे जो कुछ वजहें जिम्मेदार हों, लेकिन हकीकत (Male Nervousness) तो यही कहती है। आइए जानते हैं।

पहली डेट

हम अक्सर सोचते हैं कि डेट पर लड़कियां ही ज्यादा घबराती हैं, लेकिन असल में लड़कों को भी काफी तनाव होता है। खासकर जब वो किसी लड़की को पसंद करते हैं। उन्हें सिर्फ अपने लुक्स की ही नहीं, बल्कि पूरी डेट को लेकर चिंता होती है, जैसे कि किस रेस्तरां में जाएंगे, क्या बातें करेंगे, और कैसे इंप्रेस करेंगे। साथ ही, उन्हें ये डर भी होता है कि कहीं वो कुछ गलत न कह दें या कुछ ऐसा न कर दें जिससे लड़की नाराज हो जाए।

अपनी इमेज को लेकर

लड़के अपने दोस्तों के साथ कितनी भी मस्ती क्यों न करें, जब बात उस लड़की की आती है जिसे वे पसंद करते हैं, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। उन्हें डर लगता है कि कहीं वे कुछ ऐसा न कह दें जिससे लड़की की नजर में उनकी इमेज खराब हो जाए।

डेस्पेरेट न समझे लड़की

हम अक्सर सोचते हैं कि लड़कियां ज्यादा मौकों पर नर्वस होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड़के भी कई बार अपनी भावनाओं को लेकर काफी संकोच करते हैं? खासकर जब बात लड़कियों की आती है। पहली डेट के बाद, दोबारा मिलने के लिए पूछने में कई लड़कों को ये डर सताता है कि कहीं लड़की उन्हें 'बेताब' या 'डेस्पेरेट' न समझ ले।

प्रपोज करते समय

जब बात प्रपोज करने की आती है तो हम अक्सर लड़कियों को ही नर्वस मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लड़के भी कम नहीं होते। लड़कों को ये डर सताता रहता है कि कहीं लड़की उनकी भावनाओं को ठुकरा न दे। इसलिए, प्रपोज करने से पहले वे पूरी तरह से तैयार होना चाहते हैं और उन्हें यकीन होना चाहिए कि लड़की भी उनकी भावनाओं को समझती है।

लड़कियों से सवाल करने में

जब कोई लड़का किसी लड़की से पहली बार बात करता है तो उसे कई तरह के ख्याल चल रहे होते हैं। खासतौर से तब जब वे लड़कियों से उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ सवाल करना चाहते हैं। लड़कों को डर होता है कि कहीं उनके सवालों से लड़की असहज महसूस न करे या उन्हें डेस्पेरेट न समझे। इसलिए, फैमिली, पास्ट रिलेशनशिप जैसे निजी विषयों पर बात करते समय लड़के अक्सर नर्वस होते हैं।

आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना जनाधार खो चुकी है- देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली, - दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल का चुनावों से पूर्व दिल्लीवालों के नाम पत्र लिखने की परम्परा पिछले 11 वर्षों से चल रही है, परंतु अब दिल्ली की जनता उनके गुमराह करने वाले बयानों में फंसने वाले नही है। मैं अरविन्द केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल देते वक्त अपने आदेश में लिखा था कि उनकी 6 महीने की जांच की गिरफ्तारी उनके आरोपी होने के कारण हुई और भविष्य में उन्हें शराब घोटाले की जांच में उपस्थित होना पड़ेगा, फिर क्यों जनता को यह कहकर भ्रमित कर रहे है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नही किया। दिल्ली में पढ़ा लिखा आदमी रहता है सच और झूठ सब समझता है, अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी सरकार को बचाने की नाम, दाम, दंड भेद सब कुछ दाव पर लगा दिया है।

यादव ने कहा कि जब दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, जो कल चली जाऐगी, अरविन्द केजरीवाल को भी मालूम पढ़ गया है। आखिर भावनात्मक पत्र लिखकर केजरीवाल दिल्ली की जनता को गुमराह क्यों कर रहे है, क्या उनके सिर्फ 6 महीने जेल में रहने से दिल्ली में रहने से टूटी सड़कों की मरम्मत, सीवर सफाई, पानी सप्लाई, अस्पतालों की बदहाली जैसे काम रुकने से दिल्ली बदहाल हो गई। केजरीवाल अपनी सरकार की विफलता को स्वीकार क्यों नही करते? सड़कों पर खड़े होकर, अधिकारियों के साथ बयानबाजी करके क्या पिछले 10 वर्षों का रुका हुआ काम 4 महीने में पूरा कराना संभव है।

उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वोट मांगने जो तरीका अरविन्द केजरीवाल अपना रहे है, उससे दिल्ली का मतदाता आश्वस्त होगा या प्रताड़ति, यह सोच का विषय है। केजरीवाल पत्र में लिख रहे है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में नही आई तो फ्री बिजली बंद कर देंगे, पावर कट होगा, सरकारी स्कूलों और अस्पताल बर्बाद हो जाऐंगे, फ्री पानी बंद हो जाएगा, फ्री दवाईयां, टेस्ट, इलाज बंद हो जाऐंगे, फ्री पानी बंद हो जाएगा, महिलाओं का फ्री सफर बंद होगा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी आदि।

यादव ने कहा मैं अरविन्द केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ क्या 10 वर्ष पहले जो दिल्ली उन्हें सत्ता में मिली थी उसका 25 प्रतिशत भी बचा है। कांग्रेस ने जो 15 वर्षों में दिल्ली का विकास किया था, आम आदमी पार्टी के निष्क्रिय शासन और कार्यशैली के कारण सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल भ्रष्ट सोच और नीति ने पहले दिल्ली और पंजाब को बर्बाद कर दिया है। दोनो राज्यों की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता शासन में काम कम भ्रष्टाचार ज्यादा कर रहे है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येन्द्र जैन, संजय सिंह जेल में गए वहीं पंजाब के मंत्री भी भ्रष्टाचार में लिप्त है।

उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता काम के नाम पर आम आदमी पार्टी को वोट नही देने वाली है, क्योंकि 11 वर्षों से दिल्ली सरकार और 2 वर्षों से दिल्ली नगर निगम में काम न करके आपसी लड़ाई का जो नंगा नाच भाजपा और आम आदमी पार्टी में चल रहा है उसको दिल्ली की जनता भी भलिभांति देख रही है। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल की भविष्य से अधिक सोच का ही कारण है कि आज वो अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने में लगे है। हर प्रदेश में अधिकतर सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी का लड़ना और उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने पर केजरीवाल को भ्रम टूटता दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है, केजरीवाल पार्टी को बचाने आखिरी कोशिश कर रहे है।

ऑनलाइन पढ़ाई के साथ घर पर नीट युजी परीक्षा-2025 की तैयारी कैसे करें

विजय गर्ग

जैसे-जैसे नीट 2025 परीक्षा नजदीक आ रही है, कई इच्छुक मेडिकल छात्र अपने घरों में आराम से बैठकर कड़ी तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के उदय के साथ, उम्मीदवारों के पास अब प्रभावी स्व-अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे संसाधन और उपकरण हैं।

ऑनलाइन पढ़ाई के साथ घर पर नीट 2025 की तैयारी कैसे करें, इस पर एक व्यापक मार्गदर्शिका यहां दी गई है

1. नीट 2025 सिलेबस को समझें

तैयारी में उतरने से पहले, नीट 2025 पाठ्यक्रम से खुद को परिचित कर लें। भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में शामिल विषयों को समझें, और प्रत्येक विषय की वजन आयु के आधार पर एक अध्ययन योजना बनाएं।

2. विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म चुनें

विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म चुनें जो एनईईटी-केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। एनईईटी उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई प्रासंगिक अध्ययन सामग्री, वीडियो व्याख्यान और अभ्यास परीक्षण मददगार होंगे।

3. एक यथार्थवादी अध्ययन कार्यक्रम बनाएं

एक अध्ययन कार्यक्रम विकसित करें जो आपकी दैनिक दिनचर्या के अनुरूप हो। अपने अध्ययन सत्रों को संकेंद्रित अंतरालों में विभाजित करें, बीच-बीच में संक्षिप्त अंतराल के साथ।

4. ऑनलाइन मॉक टेस्ट का लाभ उठाएं

नियमित रूप से ऑनलाइन मॉक टेस्ट का लाभ उठाएं। ऑनलाइन कई प्लेटफ़ॉर्म हैं जो एनईईटी मॉक टेस्ट प्रदान करते हैं जो परीक्षा स्थितियों का अनुकरण करते हैं। यह न केवल आपकी प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करता है बल्कि समय प्रबंधन कौशल को भी बढ़ाता है।

5. वीडियो के माध्यम से इंटरैक्टिव शिक्षण

कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अनुभवी शिक्षकों द्वारा दिए गए वीडियो व्याख्यान पेश करते हैं। वीडियो पाठ जटिल विषयों को अधिक सुलभ बना सकते हैं और प्रमुख अवधारणाओं की आपकी समझ को बढ़ा सकते हैं।

6. त्वरित रिवीजन के लिए मोबाइल ऐप्स का उपयोग करें

ऐसे शैक्षिक ऐप्स डाउनलोड करें जो त्वरित पुनरीक्षण सामग्री प्रदान करते हैं। ऐप्स पर उपलब्ध फ़्लैशकार्ड, क्विज़ और इंटरैक्टिव अध्ययन सहायता चलते-फिरते सीखने और अंतिम समय में दोहराने के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

7. ऑनलाइन संसाधनों से अपडेट रहें

नीट से जुड़ी ताजा खबरों और बदलावों से खुद को अपडेट रखें। प्रतिष्ठित शैक्षिक वेबसाइटों का अनुसरण करें, न्यूज़लेटर्स की सदस्यता लें और परीक्षा पैटर्न या पाठ्यक्रम में किसी भी संशोधन के बारे में सूचित रहें।

8. आत्म-मूल्यांकन को प्राथमिकता दें

स्व-परीक्षणों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से नियमित रूप से विषयों की अपनी समझ का आकलन करें। कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें और उन विषयों पर अधिक समय आवंटित करें। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अक्सर आपके प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए विस्तृत विश्लेषण प्रदान करते हैं।

9. स्वस्थ अध्ययन वातावरण

घर पर एक समर्पित और आरामदायक अध्ययन वातावरण बनाएं। विकर्षणों को कम करें और अच्छी रोशनी सुनिश्चित करें। एक व्यवस्थित अध्ययन स्थान आपके फोकस और उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

10. ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करें

विषय विशेषज्ञों द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में भाग लें। कई शैक्षणिक प्लेटफ़ॉर्म लाइव सत्र आयोजित करते हैं जहां आप शिक्षकों के साथ बातचीत कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और चुनौतीपूर्ण विषयों पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

11. संतुलित जीवनशैली बनाए रखें

हालाँकि गहन तैयारी महत्वपूर्ण है, संतुलित जीवनशैली बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद लें, नियमित शारीरिक गतिविधि में संलग्न रहें और थकावट से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में ब्रेक शामिल करें। इष्टतम शिक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर आवश्यक है।

निष्कर्षतः, ऑनलाइन पढ़ाई के साथ घर पर नीट 2025 की तैयारी के लिए एक अनुशासित और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्रतिष्ठित ऑनलाइन संसाधनों का लाभ उठाकर, अपने अध्ययन कार्यक्रम के अनुरूप रहकर और एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखकर, आप आगामी नीट परीक्षा में सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

'आप' सरकार का बड़ा एलान- अब बिना डीडीए एनओसी दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मिल सकेगा बिजली का कनेक्शन

सुषमा रानी

नईदिल्ली। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब लोगों को कच्ची कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिये साझा करते हुए सीएम आतिशी ने कहा कि, भाजपा शासित डीडीए द्वारा कच्ची कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की अनिवार्यता से लोग दर दर भटकने और रिश्वत देने को मजबूर थे। लेकिन दिल्ली के 1731 कच्ची कॉलोनियों में बिजली का मीटर लगवाने के लिए लोगों की अब किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि, कच्ची कॉलोनियों में बिना एनओसी 15 दिन में बिजली कनेक्शन मिलेगा।

सीएम आतिशी ने कहा कि, दिल्ली में 1731 कच्ची कॉलोनियाँ है। 10 साल पहले तक इन कच्ची कॉलोनियों का बहुत बुरा हाल होता था। यहाँ नेता वोट मांगने तो जाते थे लेकिन जब सरकार बनती थी तो इन कच्ची कॉलोनियों में न तो सड़कें बनाई जाती थी, न पानी-सीवर की लाइनें डाली जाती थी।

सीएम आतिशी ने साझा करते हुए कहा कि, "पिछले एक साल से कच्ची कॉलोनी में रहने वाले दिल्ली के लोग बिजली कनेक्शन के लिए दर-दर भटक रहे है, ठोकरें खा रहे है। क्योंकि भाजपा शासित केंद्र सरकार की डीडीए ने एक ऑर्डर निकाला कि कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को तभी बिजली का कनेक्शन मिलेगा, जब वो डीडीए से एनओसी लेकर आते है; लिखित में लेकर आते है की वो एरिया लैंड पूलिंग के क्षेत्र में नहीं आता है।"

इसका नतीजा ये हुआ कि, पिछले एक साल से दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग जब बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करते तो उन्हें दर-दर भटकना पड़ता, एनओसी के लिए भागना पड़ता और एनओसी लेने के लिए जगह-जगह रिश्वत देनी पड़ रही थी।

सीएम आतिशी ने कहा कि, "मेरे पास बतौर ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री स्वरूप विहार एक्सटेंशन, वेस्ट कमल विहार, मोहन गार्डन, विपिन गार्डन, नवादा एक्सटेंशन सहित कई इलाकों से कई लोग अपनी शिकायतें लेकर आए। जिन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी।"

उन्होंने कहा कि, "मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि, दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि, 1731 कच्ची कॉलोनियों में बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर कोई भी व्यक्ति जो इन कॉलोनियों में रहता है वो बिजली के मीटर के लिए आवेदन कर सकता है और उन्हें डिस्कॉम्स द्वारा निर्धारित 15 दिन के समय के भीतर बिजली कनेक्शन मिलेगा।"

सीएम आतिशी ने कहा कि, भाजपा की डीडीए ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को परेशान करने की कितनी भी कोशिश कर ली लेकिन अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को परेशान नहीं होने देगी। बिजली कंपनियों को आदेश दे दिए गए है कि, अब कच्ची कॉलोनियों मीटर लगाने के लिए किसी भी एनओसी की जरूरत नहीं होगी।

दिल्ली में अपना प्रदूषण केवल एक तिहाई है, दो तिहाई प्रदूषण उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आता है- जस्मीन शाह

सुषमा रानी

नई दिल्ली। सर्दियों के मौसम में दिल्ली में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण के पीछे असली कारण पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। यह खुलासा केंद्र सरकार की एजेंसी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जारी आंकड़ों से हुआ है। वरिष्ठ नेता जस्मीन शाह ने कहा कि पूरे भारत में केवल ''आप'' की दिल्ली-पंजाब की सरकारें ही प्रदूषण कम करके जनता को राहत दिला रही हैं, बाकी सभी सरकारें सो रही हैं। खासकर दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारें प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही हैं। उन्होंने आंकड़े रखते हुए कहा कि पिछले साल के मुकाबले एक से 14 अक्टूबर तक पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 27 फीसद की कमी आई है, जबकि हरियाणा में 23 और उत्तर प्रदेश में 71 फीसद की वृद्धि हुई है। भाजपा हरियाणा और यूपी में प्रदूषण कम करने को लेकर मंभीर नहीं है। इसलिए उसने धूल प्रदूषण को कम करने के लिए भी दिल्ली की तरह कोई विंटर एक्शन प्लान नहीं बनाया है।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जस्मीन शाह ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा कि पूरे भारत में केवल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम रही आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सरकारें ही जनता को प्रदूषण से राहत दिला रही हैं। पिछले तीन दिनों से दिल्ली का एक्यूआई 200 को पार कर गया है। जोकि खराब श्रेणी है। इसका एक मुख्य कारण पराली है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाए जाने के कारण उसका प्रदूषण दिल्ली में आता है। केंद्र सरकार की एजेंसी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों से दिल्ली में पराली के वजह से होने वाले प्रदूषण का असली कारण पता चल रहा है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चल रहा है कि पराली के मुद्दे पर कौन सी राज्य सरकार लगातार काम कर रहा है और पराली जलाने की घटनाओं को कम कर रही है।

जस्मीन शाह ने कहा कि केंद्र सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 2021 में पंजाब में 71300 पराली जलाए जाने की घटनाएं पाई गई थीं। पंजाब के इतिहास में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा था। उस वक्त वहां आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। पंजाब में ''आप'' की सरकार 2022 में आई और पिछले दो सालों में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए काफी काम किया है। इसका नतीजा ये हुआ कि 2023 में पराली जलाने की घटनाएं कम होकर 36,600 हो गईं। यानि कि केवल दो सालों में कुल 50 प्रतिशत की कमी आई है। लेकिन इस साल पंजाब में 25-27 प्रतिशत पराली जलाए जाने की घटनाएं और कम होंगी। इसलिए किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि पराली के मुद्दे पर कौन सी सरकार है जो युद्धस्तर पर व निरंतर काम कर रही है और कौन सी सरकार है जो सिर्फ चैन की नींद सोने और आम आदमी पार्टी व उसके नेताओं को गाली देने का काम कर रही है।

जस्मीन शाह ने आगे कहा कि पराली केवल एकमात्र मुद्दा नहीं है जिससे दिल्ली में प्रदूषण आता है। केंद्र सरकार की एजेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के डेटा के मुताबिक, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है, उसमें से केवल एक तिहाई दिल्ली के अंदर उत्पन्न होता है। दो तिहाई प्रदूषण दिल्ली के बाहरी राज्यों से आता है, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। इसलिए केवल दिल्ली में काम करने से दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं होगा। इसके लिए केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी काम करना होगा। लेकिन अगर पिछले 10 साल का इतिहास देखा जाए तो केवल दिल्ली सरकार इस पर निरंतर काम कर रही है।

जस्मीन शाह ने कहा कि पिछले दस सालों में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कई काम किए हैं। सरकार ने दिल्ली में 2000 के करीब इलेक्ट्रिक बसें चलाई, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। डीजल की बसों से भारी मात्रा में प्रदूषण होता है। लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या शून्य है। दूसरा है, थर्मल पावर प्लांट। केवल दिल्ली की सरकार है जिसने प्रदूषण के कारण अपने सारे थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए हैं। जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं, 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने का काम केवल दिल्ली सरकार ने किया है। जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी बड़ी सोसायटी नहीं है जो डीजी बैकअप के बिना नहीं चलती है। इन राज्यों में कई ऐसी सोसायटी भी हैं जो 24 घंटे डीजल जनरेटर से चल रही हैं। वहां पर 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है।

उन्होंने निर्माण के मुद्दे पर कहा कि तमाम सरकार की रिपोर्टें कहती हैं कि करीबन एक तिहाई प्रदूषण कंट्रक्शन से आता है। इसे लेकर मंगलवार को ही आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पूरा एक प्लान शेयर किया है। जिसमें बताया गया है कि दिल्ली की सड़कों पर कुल 99 टीमें कंट्रक्शन डस्ट और कंट्रक्शन रूल को लागू करने के लिए दिन रात तैनात हैं। भाजपा बताए कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कंट्रक्शन डस्ट और कंट्रक्शन रूल का पालन सुनिश्चित करने के लिए कितनी टीमें सड़कों पर तैनात हैं? इसकी कोई सूचना नहीं है। जबकि आप के पर्यावरण मंत्री गोपल राय ने दिल्ली के लिए कुछ हफ्तों पहले 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान जारी किया है। यानि कि प्रदूषण का सीजन आने से पहले दिल्ली की सरकार ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए। उनका ना तो कोई विंटर एक्शन प्लान आया है और ना ही प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रहे हैं। उनका प्रदूषण कम करने का कोई इरादा नहीं

उन्होंने आगे कहा कि इससे साफ हो जाता है कि केवल आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं जो प्रदूषण के मुद्दे पर आक्रमक है और युद्धस्तर पर काम कर रही है। और जहां-जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वहां कोई काम नहीं हो रहा है।

राज लूंबा द्वारा लिखित "विधवा योद्धा: वह कारण जिसने मेरे जीवन को आकार दिया" किताब का अनावरण

सुषमा रानी

नई दिल्ली। ब्रिटिश काउंसिल ऑडिटोरियम में लॉर्ड राज लूंबा द्वारा लिखित "विधवा योद्धा: वह कारण जिसने मेरे जीवन को आकार दिया ₹किताब का अनावरण ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून और पूर्व राजनयिक यश सिन्हा ने किया जहां इनके अलावा सुज़ैन टोबेल, ग्राहम टोबेल, डॉ. ज्ञानेश्वर मुले, एलिसन बैरेट, लेडी वीना लूम्बा, लॉर्ड राज लूम्बा, लक्ष्मी पुरी, डॉ अरुणा अभय ओसवाल, राजीव बेरी, हरजीव सिंह एवं अमित चौधरी भी उपस्थित थे *- कल्पना कीजिए: एक छोटे से शहर पंजाब में

रहने वाला एक युवा लड़का, सात भाई-बहनों के एक खुशहाल परिवार का हिस्सा, प्यार करने वाले माता-पिता की गर्मजोशी का आनंद ले रहा है। लेकिन त्रासदी आती है और जीवन एक नाटकीय मोड़ लेता है। अपने पिता के निधन के साथ, राज लूंबा अपनी माँ, जो 37 वर्ष की कम उम्र में विधवा हो गई थी के गहरे दुःख और सामाजिक अलगाव को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। इस व्यक्तिगत दिल टूटने की घटना से उनके जीवन में मिशन का बीज बोया - एक ऐसा मिशन जो एक दिन दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल देगा।

लॉर्ड राज लूंबा की नई लॉन्च की गई किताब, ₹विधवा योद्धा: द कॉज दैट शेप्ड माई लाइफ़,₹ एक भावपूर्ण संस्मरण है जो इस उल्लेखनीय यात्रा का वर्णन करती है - करुणा, संघर्ष और विश्वास की शक्ति की कहानी। यह पाठकों को न केवल एक छोटे शहर के लड़के की मनोरंजक कहानी प्रदान करती है, जो यूनाइटेड किंगडम में धन और शक्ति के उच्च पदों पर पहुँच गया, बल्कि विधवापन से जुड़े कलंक को मिटाने के उसके अभियान का भी एक गहरा मार्मिक विवरण है। अन्याय का सामना करने के लिए लॉर्ड लूंबा की यात्रा उनकी माँ के प्रति एक व्यक्तिगत श्रद्धांजलि और बदलाव के लिए एक वैश्विक आह्वान दोनों है। उनकी चैरिटी, द लूंबा फाउंडेशन ने सैकड़ों हज़ारों लोगों के जीवन को छुआ है, लेकिन उनकी सफलता का असली शिखर 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया जाना था - विधवा भेदभाव के खिलाफ़ लड़ाई में एक ऐतिहासिक क्षण। लॉर्ड राज लूंबा कहते हैं, ₹यह सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं हैर यह उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो बहुत लंबे समय से अदृश्य रही हैं। विधवा योद्धा आशा की किरण है - यह याद दिलाता है कि बदलाव संभव है, चाहे समस्या कितनी भी गहरी क्यों न हो"_

संस्मरण का विमोचन ऐसे समय में हुआ है जब न्याय, समानता और सशक्तिकरण के विषय पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। दुनिया भर के राजनीतिक हस्तियों, व्यापारिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के समर्थन के साथ, ₹विधवा योद्धा₹ साहित्य का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा बनने के लिए नियत है - जो पाठकों को व्यक्तिगत सफलता से परे देखने और उच्च उद्देश्य की सेवा करने के आह्वान को अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

लेखक की जीवनी: पंजाब में जन्मे राज लूंबा एक सफल ब्रिटिश-भारतीय व्यवसायी हैं, जिन्होंने 1997 में निराश्रित विधवाओं का समर्थन करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। 25 वर्षों में लूंबा फाउंडेशन के शिक्षा और सशक्तिकरण कार्यक्रमों ने सैकड़ों हज़ारों विधवाओं और उनके आश्रितों के जीवन को बदल दिया है और 2010 में संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में नामित करने के लिए प्रेरित किया। अब यू.के. के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य, लूम्बा दुनिया के सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर पड़े लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भेदभाव के अभिशाप को हमेशा के लिए मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

फेस ग्रुप ने पूर्व राष्ट्रपति ए-पी-जे-अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर किया 'कलाम तुझे सलाम' का सफल आयोजन

सुषमा रानी

नईदिल्ली। विश्व भर में मिसाईल मेन के नाम से प्रसिद्ध पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 ए-पी-जे- अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के मौके पर 'कलाम तुझे सलाम' शीर्षक के तहत एक विचार गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन शकरपुर इलाके में मौजूद ट्रीपल एस- स्टूडियों में किया गया। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉ0 मुश्ताक अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज़ अहमद अंसारी एडवोकेट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहें इसके अलावा विधायक सुरेश कुमार बग्गा एडवोकेट, कृष्णा नगर ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष गुरचरन सिंह राजू ने विशिष्ठ अतिथि की हैसियत से शिरक़त की। इस मौके पर दिल्ली न्यूज़ लाइव के एडिटर सूफ़ी सैय्यद वाजिद अली, सीनियर जर्नलिस्ट एवम् फ़िल्म डायरेक्टर सुनील परासर, जर्नालिज्म टूडे ग्रुप के एडिटर जावेद रहमानी, सियासी तकदीर दैनिक के ग्रुप एडीटर मुस्तकीम खान, यमुनापार जैन समाज के प्रवक्ता विराग जैन, प्रेरणादायक प्रवक्ता प्रेरणा भाटिया आदि ने भी डॉ० कलाम की जीवन शैली पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में डोलफिन फुटवियर के चेयरमैन सैय्यद फरहत अली, सोनम बेकर्स के चेयरमैन हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, सर्वो स्टेप पॉवर के चेयरमैन मौहम्मद आलम, राय फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमित राय, प्रीत विहार आर-डब्ल्यू-ए- अध्यक्ष लॉयन गुलफाम, गीता कालोनी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जुगल किशोर, फेडरेशन ऑफ दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव देवेन्द्र जैन, समाज सेवी ज़ाहिद हुसैन, डॉ0 कमरूल हक़, फैशन डिजाईनर श्वेता जुग, सांई सहारा सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक निठारी को भी इनकी सामाजिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। मंच का संचालन उज़मा अंसारी व जैनब अंसारी द्वारा किया गया।

इस मौके पर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फिरोज़ अहमद अंसारी ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि डॉ0 कलाम का पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार पर केन्द्रित रहा, शिक्षा की बदौलत ही उन्होंने मिसाईल मैन की हैसियत से देश का नाम दुनिया में रोशन किया। उन्होंने कहा डॉ0 कलाम को सच्ची नज़राना-ए-अक़ीदत यही होगी कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराएं। विधायक सुरेश कुमार बग्गा एडवोकेट ने कहा कि गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले डॉ0 कलाम देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए यह सब शिक्षा का ही कमाल था। इस अवसर पर रितु गुप्ता, राहुल पाठक, हुमा ख़ान, अज़हर फ़िरदौसी, सोनू चंदेल, ईमानुल फ्रैंक, मेघा भारद्वाज, ज्योति जेस, आकाश पुरी, हेमंत ज़िंदानी, कंचन चौधरी, रमेश झा, पूजा श्री, तपस्या ठाकुर, अरविंद वत्स आदि गायकों ने अपनी गायकी का बेहतरीन प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की सफलता में डॉ० बिलाल अंसारी, शहाना अंसारी, शबाना अज़ीम, मीनू ठाकुर, जितेंद्र जीतू, मौ० आसिफ़, शहनाज़ अख़्तर आदि का विशेष योगदान रहा।

90 हजार अंतोदय राशन कार्ड जारी नही करने और 14.64 लाख लाभार्थियों के लंबित पड़े राशन की जांच उपराज्यपाल अपने स्तर पर कराऐ, - हारुन यूसूफ

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारुन यूसूफ ने कहा कि दिल्ली में राशन के नाम पर ढ़ोंग पूरी तरह ढ़ोंग हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा 90 हजार अंतोदय राशन कार्ड जारी नही करने की जांच उपराज्यपाल अपने स्तर पर करें और गरीबों का निवाला छीनने वाली सरकार में दोषी मंत्री/नेताओं/ अधिकारियों के खिलाफ अपराधिक मामला चलना चाहिए। उन्हांने कहा कि यह भी जांच की मांग की कि 10 सालों में 14.64 लाख लाभार्थियों के राशन कार्ड क्यों लंबित पड़े है जबकि हर वर्ष 4-5 लाख दिल्ली की जनसंख्या बढ़ जाती है। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनसंख्या 2.5 करोड़ से अधिक हो गई है, जिनमें लगभग 40 प्रतिशत अत्यंत गरीब लोग है।

संवाददाता सम्मेलन को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी संबोधित किया।

हारुन यूसूफ ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर तय किया 2012-13 में दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड लोगों को देने की संख्या निश्चित करके उन्हें 2 रुपये किलो गेहू और 3 रुपये किलो चावल देना सुनिश्चित किया गया और अन्नश्री योजना के तहत अत्यंत बीपीएल और अंतोदय गरीबों को खाद्य सामग्री के लिए 600 रुपये प्रत्येक सदस्य और परिवार के खाते में 4800 रुपये देने की योजना बनाई जिसके तहत तुरंत 2 लाख गरीबां के लिए लागू की गई। 2014 में सत्ता आने के बाद से ही केजरीवाल सरकार ने गरीबों को मिलने राशन में कटौती करके गरीब दिल्लीवालों को मुफ्त राशन का सब्जबाग दिखाकर उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि यह दिल्लीवालां का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 वर्षों एक भी नया राशन कार्ड नही बना और न ही जन्में बच्चे का नाम जुड़ा है और न मरने वाले का नाम कटा है,

मतलब राशन विभाग पूरी तरह निष्क्रिय रहा है।

अ0भा0क0 कमेटी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि राजधानी में राशन वितरण प्रणाली बहुत बड़े घोटाले से जुड़ा विषय है जिसमें केन्द्र में भूखों की सरकार है जो कहती है 80 करोड़ लोगों को खाना मुफ्त देते है, दूसरी दिल्ली में ठगों की सरकार है जो दिल्लीवालों को मुफ्त राशन देने की बात तो करती है परंतु राशन गरीबों तक पहुँचता नही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में आते ही राशन वितरण का बंटाधार कर दिया। उन्होंने कहा कि 2015 में 2400 राशन की दुकाने थी, जो 10 वर्षों में 500 कम हो गई है। उन्होंने कहा कि 2013 में 34.55 लाख राशन कार्ड थे जो अब घटकर 17.83 लाख रह गए है।

आलोक शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा जनवरी 2024 में यह आदेश हुआ कि दिल्ली में राशन मिलने के लिए लाभार्थियों की संख्या कितनी है, इसके आंकड़े तैयार किए जाए परंतु अभी साल खत्म होने वाला है, दिल्ली के गरीब लोगों के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट 7 में गरीबों को राशन न दिए जाने की स्थिति में उनके खाते में सीधा राशि देने का प्रावधान किया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली में गरीबों को न राशन दिया और न ही लाभार्थियों के खाते में कोई राशि दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्लीवालों को राशन दिया ही नही है, अपनी सरकार होने के बावजूद सिर्फ 10 वर्ष से काम न करने का आरोप दूसरों पर लगाते हुए दिखाई दिए है।

डॉ. के लक्ष्मण को संगठनात्मक चुनाव के लिए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी बनना गौरव की बात:पेरिका सुरेश

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नईदिल्ली। ओबीसी मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी परिका सुरेश ने ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण को संगठन चुनाव के संचालन हेतु राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी बनाए जाने पर अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हुए कहा कि एक योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति को पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। श्री सुरेश ने कहा कि डॉक्टर लक्ष्मण पार्टी के समर्पित नेता हैं। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे देश में ओबीसी समाज को संगठित करने का काम किया है। उनके कार्यों एवं पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हैं। श्री सुरेश ने कहा कि दक्षिण भारत को भाजपा जिस तरह से महत्व दे रही है और वहां के राजनेताओं पर बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है उससे दक्षिण भारत में भाजपा का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक इमानदार कर्मठ और

अनुभवी नेता के रूप में डॉक्टर के. लक्ष्मण की अपनी खास पहचान है। उनके प्रयास से कई राज्यों के चुनाव में ओबीसी समाज संगठित होकर भाजपा के पक्ष में वोट किया और उन राज्यों में भाजपा की सरकार बनी।

कठघरे में यमुना प्राधिकरण की ये योजना, धीरे-धीरे खुलने लगे बड़े राज; फंस सकते हैं अधिकारी

परिवहन विशेष न्यूज

यमुना प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना विवादों में घिर गई है। आवेदकों ने पात्रता तय होने के बाद भी सामान्य श्रेणी में शामिल किए जाने को कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में वाद दायर होने से प्राधिकरण के अधिकारी सकते में हैं। बताया गया कि नौ आवेदनकर्ता सक्रिय हुए और उन्होंने इस मामले में आवाज उठाई है।

नोएडा। YEIDA धीरे-धीरे ही सही, लेकिन अब यमुना प्राधिकरण में भूखंड आंवटन (Yeida Plot Scheme) को लेकर अधिकारियों और बिचौलियों के बीच गहरी सांठगांठ की कलई खुलने लगी है। आवंटियों ने अधिकारियों से कुछ कहने की बजाए कार्यप्रणाली को अदालत में चुनौती देना शुरू कर दिया है।

ताजा मामला यमुना प्राधिकरण में आवासीय भूखंड आवंटन ड्रा से जुड़ा प्रकाश में आया है, जिसमें आरक्षित कोटे में आवेदन करने वाले पात्र आवंटियों को ड्रा से ठीक पहले जबरन सामान्य श्रेणी में शामिल दिया गया, जानकारी मिलते ही तत्काल नौ आवेदनकर्ता सक्रिय हुए और अधिकारियों की इस हरकत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली, जिससे तत्काल वाद दाखिल होने से अधिकारी फंस गए।

361 भूखंड की जगह 352 भूखंड को किया गया शामिल

यमुना प्राधिकरण ने ड्रा निर्धारित तिथि 10 अक्टूबर को आयोजित कराया, लेकिन विभिन्न श्रेणी 361 भूखंड की जगह 352 भूखंड को शामिल किया गया। नौ भूखंड का ड्रा रोकना पड़ा। इससे ड्रा की पूरी प्रक्रिया ही कटघरे में खड़ी हो गई। अब प्राधिकरण अधिकारी इन नौ आवेदनकर्ताओं पर आरोप लगा रहे है कि इन्होंने ब्रोशर शर्त का उल्लंघन किया है।

हाईकोर्ट जाने वाले आवेदनकर्ताओं ने बताया कि यमुना प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड की योजना पांच जुलाई सेक्टर-16, 18, 20, 22 डी के लिए आवासीय योजना निकाली गई थी। पांच अगस्त को योजना बंद कर दी गई। योजना में औद्योगिक, संस्थागत व वाणिज्यिक श्रेणी में फंक्शन करान लेने वाले आवेदकों को पांच प्रतिशत भूखंड आवंटित किया गया था।

25 सितंबर तक जवाब दाखिल करना था

इसमें विभिन्न वर्ग मीटर में 18 भूखंड शामिल रहे। 17 सितंबर को पात्रता तय करनी शुरू हुई। 18 सितंबर को लिस्ट लगा दी गई। 25 सितंबर तक जवाब दाखिल करना था। 30 को सितंबर को पात्रता का निस्तारण कर दिया गया, लेकिन तीन अक्टूबर को रात साढ़े 10 बजे ऑनलाइन लिस्ट डाली गई, जिसमें वाणिज्यिक श्रेणी के सभी लोगों को सामान्य श्रेणी में शामिल कर दिया गया।

बताया गया कि यह सबकुछ बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया, क्योंकि चार अक्टूबर के बाद हाईकोर्ट में दशहरा पर्व का अवकाश शुरू होना था, कोर्ट 15 अक्टूबर को कोर्ट खुलती है, तब तक देर हो जाती। इसलिए तीन अक्टूबर देर रात से आवासीय

भूखंड ड्रा को लेकर वकीलों से संपर्क साधा गया, हाईकोर्ट के लिए वाद दाखिल करने का प्रयास शुरू हुआ। चार अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका डाल प्राधिकरण काउसिंल का रिसीव करा दी गई।

यही नहीं, गौतमबुद्धनगर में भी यमुना प्राधिकरण में वाद का कागजी दस्तावेज रिसीव करा दिया गया, जिसके बाद प्राधिकरण ने नौ भुखंड रोकर बाकी का ड्रा करा दिया।

उधर, आवेदनकर्ताओं ने बताया कि आवासीय भूखंड योजना में शर्त थी कि यदि यमुना से कोई वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक भूखंड आवंटित है, तो वह पांच प्रतिशत आरक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकता है। यमुना प्राधिकरण ने बिल्डअप क्योस्क की योजना वर्ष 2021 में निकाली थी।

बता दें कि 9.04 वर्ग मीटर का क्योस्क आठ लाख का था, जिसे बोली लगाकर नीलामी में 21 लाख रुपये में आवंटित कराया गया, जिसकी चेक लिस्ट 14 मार्च 2024 को जारी की गई। पांच मई को अलॉटमेंट लेटर मिला। 25 जुलाई को कब्जा लिया और जुलाई में फंक्शन का सर्टिफिकेट मिल गया।

भूखंड (वर्ग मीटर)-भूखंड संख्या-कृषक श्रेणी (17.5 प्रतिशत)-फंक्शनल औद्योगिक, वणिज्यिक, संस्थागत (5 प्रतिशत)-सामान्य श्रेणी (77.5 प्रतिशत)

120-84-15-04-65
162-77-13-04.60
200-03-01-00-02
300-131-23-07-101
500-40-07-02-31
1000-18-03-01-14
4000-08-01-00-07

आरक्षित कोर्ट से जिन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल किया गया है। उन्होंने जीएसटी की जानकारी से अवगत नहीं कराया है, न ही माप तौल विभाग का प्रमाण पत्र जमा कराया है। हालांकि नौ भूखंड रोककर ड्रा सपन्न कराया गया है। - डा अरूणवीर सिंह, सीईओ, यमुना प्राधिकरण

वाणिज्यिक श्रेणी में 300 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड के लिए आवेदन किया था। पात्रता तय होने के बाद जबरन तीन अक्टूबर को सामान्य श्रेणी में शामिल कर दिया गया, कारण अधिकारियों ने नहीं बताया। जबकि शाप एक्ट के तहत सभी दस्तावेज आवेदन के साथ जमा है। - मंयक गुप्ता, आवंटी, यमुना प्राधिकरण

तीनों प्राधिकरणों में लगातार भूखंड नीती कटघरें में खड़ी हो रही है। औद्योगिक संगठनों की इस प्रकरण में मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं होने से अधिकारियों के हौसले बुलंद है। -सुधीर श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन

दिल्ली और नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर, सुगम होगा आवागमन; 105 करोड़ की फाइल हुई पास

राजधानी दिल्ली और नोएडा वालों के लिए एक अच्छी खबर है। नोएडा प्राधिकरण ने चिल्ला एलिवेटेड रोड की फाइल को 105 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत के साथ लखनऊ वित्त समिति को भेज दिया है। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना से दिल्ली और नोएडा के बीच आवागमन सुगम होगा। आगे विस्तार से पढ़िए पूरी खबर।

नोएडा। दीपावली के बाद चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो सकता है। इसके संकेत मिलने लगे है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम ने 105 करोड़ की फाइल पर एप्रूवल देकर वित्तीय समिति शासन को भेज दी है। वित्तीय समिति की ओर से अध्ययन करने के बाद फाइनल अनुमति मिल मिल जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश सेतु निगम चयनित कंपनी के साथ अनुबंध साइन करेगा। निर्माण कार्य शुरू कराएगा।

वित्तीय समिति के पास भेजी थी फाइल

बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड की ओर से परियोजना में 153 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आने की संभावना जताई थी, जिसके बाद प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम ने शासन से मार्ग दर्शन व अतिरिक्त लागत की मंजूरी की अनुमति के लिए पत्र लिखा था, जिससे मिले गाइडेंस के बाद सीईओ ने 105 करोड़ की फाइल को वित्तीय समिति के पास भेज दिया है।

बता दें कि शहदरा ड्रेन के ऊपर से दिल्ली स्थित चिल्ला रेगुलेटर से नोएडा के महामाया फ्लाईओवर तक 5.5 किलोमीटर का चिल्ला एलिवेटेड रोड बनाया जाना है। इसको दिल्ली के मयूर विहार फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा। निर्माण के लिए अप्रैल 2023 में यूपी कैबिनेट ने जीएसटी सहित 787 करोड़ 31 लाख 82 हजार रुपये की लागत को मंजूरी दे दी थी।

इस साल करीब छह माह पहले उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखकर कहा कि इस परियोजना पर करीब 153 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्चा आएगा। अलग-अलग मद में कुल 937 करोड़ 90 लाख 86 हजार रुपये खर्चा आना बताया। यह लागत मंजूर होने के बाद ही मौके पर काम शुरू हो सकेगा।

नोएडा प्राधिकरण ने शासन स्तर से सुझाव मांगा था

इस पत्र का हवाला देते हुए नोएडा प्राधिकरण ने शासन स्तर से सुझाव मांगा था, जिसके बाद 105 करोड़ अतिरिक्त फाइनल किया गया। सेतु निगम की तरफ से और मांगे जा रहे करीब 46 करोड़ रुपये की राशि को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब कुल 892 करोड़ 75 लाख 34 हजार रुपये की लागत से एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा।

अब प्राधिकरण इस संबंध में सेतु निगम को पत्र भेजकर आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहेगा। इस साल दिसंबर तक काम शुरू कराने की तैयारी है। एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए सेतु निगम टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। इसको बनाने का जिम्मा एमजी कांट्रेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है।

इस परियोजना का निर्माण कराने के लिए लोक निर्माण विभाग खुद आगे आया था। लोक निर्माण विभाग की तरफ से नोएडा प्राधिकरण को 27 अगस्त 2018 को पत्र भेजते हुए बताया गया कि इस काम के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

इस परियोजना पर आने वाले खर्चे के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि प्रदेश सरकार और 50 प्रतिशत राशि नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा। पत्र के बाद सेतु निगम व प्राधिकरण के बीच 18 जनवरी 2019 को एमओयू हुआ था।

गुरुग्राम में धड़ाधड़ कट रहे चालान, सिर्फ 15 दिनों में 25 हजार वाहनों पर कार्रवाई

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। सितंबर के आखिरी 15 दिनों में 20 हजार से ज्यादा रॉन्ग साइड वाहनों के चालान किए गए। वहीं लेन ड्राइविंग की अवहेलना करने पर 4422 वाहनों के चालान किए गए। इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव में 412 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।

गुरुग्राम। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई जारी है। विपरीत दिशा से वाहन चलाने वालों के खिलाफ दैनिक जागरण की ओर से हर सप्ताह चलाए जा रहे अभियान को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आई।

ट्रैफिक पुलिस ने सितंबर के आखिरी 15 दिनों में 20 हजार से ज्यादा रॉन्ग साइड वाहनों के चालान किए। जबकि सितंबर के पहले 15 दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ 5700 चालान किए थे।

हरकत में आई गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस

डीएलएफ फेस दो मेट्रो स्टेशन के पास 15 सितंबर को रॉन्ग साइड आई कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। इस मामले ने सोशल मीडिया पर काफी तूल पकड़ा। आरोपित कार चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था।

इस हादसे के बाद दैनिक जागरण की ओर से हर सप्ताह विपरीत दिशा से वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसको देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आई।

15 सितंबर तक हुए थे करीब 5700 चालान

ट्रैफिक डीसीपी विरेंद्र विज के निर्देश पर अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन कर विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया। जहां रॉन्ग साइड वाहनों के 15 सितंबर तक करीब 57 सौ चालान किए गए थे, वहीं अब पूरे महीने में विपरीत दिशा से चलने वाले 26700 वाहनों पर कार्रवाई की गई।

एक करोड़ 59 लाख आठ हजार 500 रुपये का फाइन

इसकी कुल जुर्माना राशि करीब एक करोड़ 59 लाख आठ हजार 500 रुपये है। जबकि अगस्त में ट्रैफिक पुलिस ने 16 हजार रॉन्ग साइड वाहनों के चालान किए थे।

लेन-ड्राइविंग की अवहेलना करने पर 4422 वाहनों के चालान

ट्रैफिक पुलिस ने बीते दिनों लेन ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए गलत लेन में ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया। इस दौरान चार हजार से अधिक वाहनों के चालान किए गए। ट्रैफिक डीसीपी विरेंद्र विज ने बताया कि विशेष अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम पुलिस ने सही लाइन में ड्राइविंग नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ड्रोन की सहायता से मॉनिटरिंग की।

35 लाख 11 हजार रुपये है जुर्माना राशि

लेन ड्राइविंग की अवहेलना करने वाले कुल 4,422 वाहन चालकों के चालान किए गए। इनकी कुल जुर्माना राशि 35 लाख 11 हजार रुपये है। विज ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य ट्रैफिक का संचालन व्यवस्थित व सुगम बनाकर गुरुग्राम की सड़कों पर वाहनों का संचालन सुरक्षित करना है।

सड़क हादसों का एक मुख्य कारण गलत लेन में वाहन चलाना तथा अचानक लेन बदलना भी है। इसमें स्वयं और दूसरों की जान-माल को क्षति पहुंचती है। वाहन चालकों के लिए लेनों को पृथक करने के लिए अक्सर सड़क पर चिन्ह बना दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी नियमों का उल्लंघन करते हैं।

ड्रिंक एंड ड्राइव में 412 वाहन चालकों पर कार्रवाई

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। डीसीपी ट्रैफिक विरेंद्र विज के निर्देश पर अलग-अलग टीमों को तैनात कर बीते दिनों अभियान चलाया गया।

इस दौरान नाका लगाकर चेकिंग करते हुए चार महिलाओं समेत 412 वाहन चालक ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए मिले। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए चालान किए गए। एक वाहन को जब्त भी किया गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सौ वर्षीय यात्रा पर एक नजर

डा.हेडगेवार ने संगठन को देश की राष्ट्रीय आवश्यकता कहा था। उन्होंने कोलकाता में क्रांतिकारियों और नागपुर में कांग्रेस के साथ काम कियाय पर संघ स्थापना के बाद पूरी शक्ति यहीं लगा दी। इसलिए पहले 50 साल संघ ने केवल संगठन किया।

2025 की विजयादशमी पर संघ सौवें वर्ष में पहुंच रहा है। ऐसे में इस यात्रा के कुछ पड़ावों पर नजर डालना उचित होगा।

डा. हेडगेवार ने संगठन को देश की राष्ट्रीय आवश्यकता कहा था। उन्होंने कोलकाता में क्रांतिकारियों और नागपुर में कांग्रेस के साथ काम कियाय पर संघ स्थापना के बाद पूरी शक्ति यहीं लगा दी। इसलिए पहले 50 साल संघ ने केवल संगठन किया। यद्यपि अन्य बहुत कुछ भी शीर्ष नेतृत्व के मन में था। दत्तोपंत ठेंगड़ी इसे 'प्रोगेसिव अनफोल्डमेंट' कहते थे। इसके बल पर ही संघ ने हर संकट को झेला।

इस पहले दौर में स्वयंसेवकों ने कई संस्थाएं बनायीं। इनमें राष्ट्र सेविका समिति (1936), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (1949), वनवासी कल्याण आश्रम (1952), भारतीय मजदूर संघ (1955), विश्व हिन्दू परिषद (1964), भारतीय जनसंघ/भारतीय जनता पार्टी (1951), सरस्वती शिशु मंदिर/विद्या भारती (1952) आदि प्रमुख हैं। यद्यपि इनके संविधान, कोष, पदाधिकारी, कार्यक्रम आदि अलग हैंय पर प्रेरणा संघ की ही है।

संघ पर प्रतिबंधः संघ पर 1932 और 1940 में शासन ने आंशिक प्रतिबंध लगायेय पर वे ज्यादा नहीं चले। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद फिर प्रतिबंध लगा। तब शासन, प्रशासन और जनता संघ के विरोध में थी। प्रचार माध्यम सरकार के पास थे। संघ के पास अपनी बात कहने का कोई साधन नहीं था। फिर भी संघ ने सत्याग्रह से सरकार को झुका दिया।

पर फिर शाखा के साथ ही समविचारी संगठनों का विस्तार और प्रभाव बढ़ने लगा। इसीलिए जब 1975 में इंदिरा गांधी ने संघ पर प्रतिबंध लगाया, तो जनता संघ के साथ रही। संघ ने फिर सत्याग्रह किया। जनता डर से चुप थी, पर चुनाव में उसका आक्रोश फूट पड़ा और इंदिरा गांधी हार गयी। यह संगठन के बल पर ही हुआ। समाज में बढ़ती स्वीकार्यता का लाभ उठाकर संघ ने संगठन को फैलाया तथा स्वयंसेवकों ने अनेक नयी संस्थाएं बनायीं।

1992 में बाबरी विध्वंस के बाद सरकार ने फिर प्रतिबंध लगाया, जिसे न्यायालय ने ही खारिज कर दिया। 1975 और 1992 के प्रतिबंध से संघ के संगठन और प्रभाव में वृद्धि हुई। उसका नाम दुनिया भर में फैल गया।

1977 के बादः इसे हम दूसरा 50 वर्षीय कालखंड कह सकते हैं। संघ ने अनुभव किया कि हमारा काम समाज के निर्धन वर्ग में नहीं है। इनकी पहली जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है। इस कारण लोग धर्मांतरण भी कर लेते हैं। मीनाक्षीपुरम् कांड इसका उदाहरण था। अतः सेवा के क्षेत्र में प्रवेश किया गया। 1989 में डा. हेडगेवार की जन्मशती पर 'सेवा निधि' एकत्र कर हजारों पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनाये गये। निर्धन बस्तियों को 'सेवा बस्ती' कहकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हजारों छोटे प्रकल्प शुरू किये। अब इनकी संख्या डेढ़ लाख से भी अधिक है। अब सैकड़ों बड़े प्रकल्प भी हैं, पर मुख्य ध्यान छोटी इकाइयों पर ही है। केवल संघ ही नहीं, तो सभी समविचारी संस्थाएं सेवा कार्य कर रही हैं। यहां से पुरुष और महिला कार्यकर्ता भी आगे आ रहे हैं।

कुछ चुनौतियांः 1947 में देश विभाजन एक बड़ी चुनौती थी। इस दौरान पंजाब और सिंध में संघ ने सीमित शक्ति के बावजूद लाखों हिन्दुओं की रक्षा की, महिलाओं की लाज बचाई और उनका पुनर्स्थापन किया। बंगाल में शक्ति कम होने से यह प्रभावी ढंग से नहीं हो सका।

1950 में प्रतिबंध हटने पर कुछ लोगों का विचार था कि निर्दोष होते हुए भी संसद या किसी विधानसभा में कोई हमारे पक्ष में नहीं बोला। अतः हमें शाखा छोड़कर केवल राजनीति करनी चाहिएय पर सरसंघचालक श्री गुरुजी नहीं माने। उन्होंने कहा कि राजनीति जरूरी होते हुए भी सब कुछ नहीं है। इससे कई बड़े लोग नाराज हो गये। यद्यपि संघ ने फिर राजनीति में भी कई लोगों को भेजा, पार्टी भी बनायी, पर राजनेताओं और दलों का जो हाल है, उससे श्री गुरुजी की बात प्रमाणित हो रही है।

संगठन होने के कारण संघ तथा संघ प्रेरित संस्थाएं लगातार नयी टीम बनाकर पुरानों के संरक्षण में उन्हें पदस्थापित करते रहते हैं, पर 1968 में भारतीय जनसंघ को एक झटका लगा। दीनदयाल जी का निधन हो चुका था। जनसंघ वाले अटल बिहारी वाजपेयी को आगे लाना चाहते थे। इससे रुष्ट होकर बलराज मधोक ने पार्टी छोड़ दी, पर जल्दी ही वे समझ गये कि कुछ लोग कुछ समय के लिए कोई संस्था तो चला सकते हैं, पर संगठन नहीं। अतः वे शांत होकर फिर संघ के कार्यक्रमों में आने लगे। यद्यपि उनके अलगाव से श्री गुरुजी सहित सब स्वयंसेवकों को दुख हुआ, पर संघ में व्यक्ति नहीं, संगठन महत्वपूर्ण है।

ऐसी ही एक चुनौती 2018 में विश्व हिन्दू परिषद में आयी। एक प्रभावी नेता ने अपनी नयी संस्था बना ली। यहां भी टकराव व्यक्ति और संगठन में ही था। आशा है वे भी शीघ्र ही मुख्य धारा में लौट आएंगे।

अब आगे की ओरः कभी 'संगठन के लिए संगठन' की बात कही जाती थी, पर 50 साल संगठन और 50 साल विस्तार के बाद अब संघ समाज परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। जहां संघ का काम पुराना है, वहां परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग, सामाजिक समरसता, एक मंदिर, एक शमशान, एक जलस्रोत, नागरिक कानूनों के पालन आदि का आग्रह किया जा रहा है। संघ के प्रयास से इस दिशा में भी निःसंदेह सुधार होगा। समाज में हजारों संस्थाएं और लोग अच्छे काम कर रहे हैं। संघ उन्हें भी साथ लेकर सम्मान और श्रेय देता है। संस्थागत अभिनिवेश से मुक्ति संघ की एक बड़ी विशेषता है।

यद्यपि जब से भाजपा की सरकारें केन्द्र और राज्यों में बन रही हैं, तब से संघ में बहुत भीड़ भी आने लगी है। नये लोगों का आना सुखद है, पर जो स्वार्थवश आ रहे हैं, उनसे सावधान रहना होगा। 'नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे' से लेकर 'परम वैभवं नेतुमेतत्स्वराष्ट्र' की इस अविराम यात्रा में बहुत काम बाकी है। निरूसंदेह अगले कुछ वर्ष में करोड़ों स्वर 'भारत माता की जय' बोलेंगे और विश्वगुरु भारत का सपना साकार होगा।

लापरवाही की तो नपेंगे जिम्मेदार, लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर सरकार का आदेश जारी

गौतमबुद्ध नगर में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर नियमावली 2024-25 सितंबर 2024 से लागू कर दिया गया है। अब लिफ्ट खराब हुई तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। इसमें संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एडीएम वित्त एवं राजस्व नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारीअधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा को संयोजक के तौर पर रखा गया है।

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में सोसायटीज, सेक्टर सहित बड़े मॉल, कार्यालयों में लिफ्ट व एस्केलेटर की सुरक्षा, अनुरक्षण, संचालन के लिए उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली 2024 को 25 सितंबर 2024 से प्रभावी कर दिया गया है।

इसको लेकर डीएम के पास जीओ भी आ गया है। जिसमें डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष,एडीएम वित्त एवं राजस्व ,नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी,अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सहायक निदेशक विदयुत सुरक्षा को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।

लिफ्ट दुर्घटना पर होगी कार्रवाई

यह सदस्य लिफ्ट व एस्केलेटर संबंधित अनुरक्षण, सुरक्षा व संचालन को लेकर हो रही गतिविधियों, किसी दुर्घटना पर समुचित कार्रवाई की रिपोर्ट डीएम को देंगे। जागरण ने मंगलवार के अंक में लिफ्ट की सुरक्षा को लेकर खबर का प्रकाशन किया था कि जीओ जारी न होन से कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली के लागू हो जाने से प्रशासन को कार्रवाई करने में आसानी होगी और लोगों को न्याय मिल सकेगा।

पांच सदस्यीय समिति का हुआ गठन

प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण की तरफ से 25 सितंबर 2024 को जारी किए गए शासनादेस में के नियम नौ में प्रावधान किया गया है कि लिफ्ट, एस्केलेटर से संबंधित दुर्घटना लागबुक अनुरक्षित करने की व्यवस्था की जिम्मेदारी संचालक की होगी।

यह लॉग बुक आधिकारिक तौर पर स्थानीय सहायक निदेशक विद्त सुरक्षा या अधिकारिता वाले किसी अन्य विदयुत निरीक्षक या स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से अधिकृत किसी कार्यकारी अधिकारी के मांगे जाने पर इसे देना होगा।

गठित की गई पांच सदस्यीय समिति की त्रैमासिक बैठक की जाएगी। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि शासनादेस उनको आज ही मिला है। इसमें जो भी नियम हैं उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

महाराष्ट्र के पिंक ई-रिक्शा कार्यक्रम के तहत काइनेटिक ग्रीन को मिला ₹400 करोड़ का ठेका

परिवहन विशेष न्यूज

महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अपने उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत पुणे स्थित काइनेटिक ग्रीन एनर्जी पावर सॉल्यूशंस को ₹400 करोड़ का ठेका दिया है। इस पहल के तहत राज्य के आठ शहरों में महिला चालकों के लिए 10,000 गुलाबी ई-रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें पुणे, नासिक, नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर और संभाजीनगर शामिल हैं।

काइनेटिक ग्रीन के साथ राज्य सरकार के आशय पत्र (एलओआई) में पुणे को 4,000 ई-रिक्शा, नासिक को 1,000, नागपुर को 2,000 और अन्य शहरों में से प्रत्येक को 600 ई-रिक्शा आवंटित किए गए हैं। ई-रिक्शा को भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। एलओआई के अनुसार प्रत्येक ई-रिक्शा की कीमत 3,73,003 रुपये है, जिसमें चार्जिंग स्टेशन सहित काइनेटिक ग्रीन की ओर से पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन शामिल होगा।

यह निर्णय आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले आया है, क्योंकि राज्य 20 नवंबर, 2024 को चुनावों की तैयारी कर रहा है। काइनेटिक ग्रीन को इस परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में चुना गया था।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस साल के राज्य बजट में घोषित पिंक ई-रिक्शा योजना के अनुसार सभी बेरोजगार महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा खरीदने पर 20% तक की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के माध्यम से, पात्र महिलाएं शुरुआत में कुल लागत का केवल 10% भुगतान करके ई-रिक्शा खरीद सकती हैं।

भारत में वॉल्यूम के मामले में ई-टू-व्हीलर सेगमेंट सबसे बड़ा है, लेकिन ई-थ्री-व्हीलर सबसे तेज़ी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। इस साल अगस्त में सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन वाले कुल 105,478 थ्री-व्हीलर बेचे गए। 60,714 यूनिट्स के साथ, ई-थ्री-व्हीलर्स कुल का 57% हिस्सा थे, जिसका मतलब है कि थ्री-व्हीलर सेगमेंट में हर दूसरी यूनिट ईवी थी।

अगस्त 2024 में बेचे गए कुल इलेक्ट्रिक वाहनों में से ई-थ्री-व्हीलर्स की हिस्सेदारी 39% होगी।

जैव ईंधन भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और हमारे किसानों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने की कुंजी : नितिन गडकरी

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सोमवार 14 अक्टूबर को 12वें सीआईआई जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में "भविष्य को ईंधन प्रदान करना – भारत के हरित विकास लक्ष्यों को सुरक्षित करना" विषय पर इथेनॉल मिश्रण और जैव ईंधन पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित किया।

भारत में इथेनॉल मिश्रण की सफलता पर प्रकाश डालते हुए गडकरी ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 2014 में 1.53% से बढ़कर 2024 में 15% हो गया है, जिसे 2025 तक 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की सरकार की रणनीति के तहत, डीजल में भी 15% इथेनॉल मिश्रण की संभावना तलाशने के लिए अनुसंधान भी चल रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने इथेनॉल इकोसिस्टम के निर्माण पर जोर दिया, जिसमें चार राज्यों- कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा 400 इथेनॉल पंपों की स्थापना शामिल है। इथेनॉल से चलने वाली फ्लेक्स-इंजन वाली कारों को लॉन्च करने की योजना पर प्रमुख वाहन विनिर्माताओं के साथ चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह

दोपहिया वाहनों के प्रमुख विनिर्माता बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद इथेनॉल से चलने वाली बाइक लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं।

गडकरी ने कहा, "हम इन चार प्रमुख राज्यों में इथेनॉल उत्पादन और वितरण बढ़ाने के प्रयासों को तेज़ कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि ये पहल भारत के व्यापक जैव ईंधन लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जो देश को टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में अग्रणी बना देगी।

गडकरी ने खास तौर पर चावल के भूसे से बायो-सीएनजी के उत्पादन सहित अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाली तकनीकों का लाभ उठाने के महत्व पर भी चर्चा की, जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में पहले ही चालू हो चुकी 40 से ज्यादा परियोजनाओं के साथ-साथ 475 परियोजनाओं में व्यवहार्य साबित हुई है। चावल के भूसे को सीएनजी में बदलने जाने का अनुपात लगभग 5:1 टन है। केंद्रीय मंत्री ने कुशल बायोमास स्रोतों और बायोमास के लागत प्रभावी परिवहन पर और अधिक शोध करने का आह्वान किया।

पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से संबंधित पर्यावरणीय चुनौती पर बोलते हुए श्री गडकरी ने इंडियन ऑयल के पानीपत प्लांट की प्रशंसा की, जो कृषि अपशिष्ट (पराली) को बायोमास में बदल रहा है। उन्होंने कहा, ₹फिलहाल हम पराली का पांचवां हिस्सा ही प्रोसेस कर पाते हैं, लेकिन उचित योजना बनाकर हम पराली जलाने से होने वाले मौसमी वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम कर सकते हैं।₹

केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) ने जैव-बिटुमेन (डामर) के उत्पादन पर किए गए शोध से आयातित बिटुमेन पर भारत की निर्भरता कम होने का भी वादा किया है, जो देश के हरित विकास एजेंडे में और योगदान देगा।

श्री नितिन गडकरी ने वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत के 22 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक जीवाश्म ईंधन आयात को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "जैव ईंधन भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और हमारे किसानों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने की कुंजी है।"

अंत में, उन्होंने किसानों की भूमिका को "अन्नदाता" (खाद्य-दाता) से "ऊर्जादाता" (ऊर्जा-दाता), "ईंधनदाता" (ईंधन-दाता) और अंततः ₹हाइड्रोजन-दाता₹ (हाइड्रोजन-दाता) तक विस्तारित करने में जैव ईंधन क्षेत्र की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने समिट के आयोजन के लिए सीआईआई को बधाई दी।

पीयूष गोयल ने निर्माताओं से निर्यात के लिए गुणवत्ता पर ध्यान देने का किया आग्रह

परिवहन विशेष न्यूज

पीयूष गोयल ने देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र से भारत में निर्मित उत्पादों के गुणवत्ता मानकों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है।

गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सब्सिडी या सरकारी समर्थन से या शेष विश्व के लिए दरवाजे बंद करने से नहीं आएगी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने बुधवार, 16 अक्टूबर को भारतीय गुणवत्ता प्रबंधन फाउंडेशन की संगोष्ठी में कहा, ₹अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो यह तभी संभव है जब हम आत्मविश्वासी हों और यह आत्मविश्वास तभी आएगा जब हम सभी यह तय करेंगे कि गुणवत्ता हमारा काम नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है।₹ इसके संस्थापक सदस्यों में मदरसन ग्रुप, टीवीएस मोटर कंपनी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, बोइंग, लार्सन एंड टर्बो और बायोकॉन शामिल हैं।

उन्होंने कहा, ₹अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाना, अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा देना अब हममें से किसी के लिए विकल्प नहीं रह गया है। यह सिस्टम पर डिफ़ॉल्ट विकल्प है। उद्योग के केंद्र में गुणवत्ता को लाना समय की मांग है, इससे मानसिकता बदलने में मदद मिलती है।₹

ऑटोमोबाइल क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में से एक है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7% से अधिक का योगदान देता है तथा भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कई वैश्विक ऑटो कंपनियां अब भारत को घरेलू बिक्री के साथ-साथ निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देख रही हैं, क्योंकि वे चीन से परे एक विश्वसनीय और कम लागत वाले आधार की तलाश कर रही हैं।

सरकार ऑटोमोबाइल क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने तथा भारत को ऑटोमोबाइल का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्सुक है, तथा उसने घरेलू विनिर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।

मंत्री ने यह भी कहा कि घटक निर्माता सभी मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में सक्रिय रहे हैं, और वे वैश्विक खिलाड़ियों से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा से डरते नहीं हैं।

गोयल इस दशक के अंत तक ऑटो कम्पोनेंट निर्यात को पांच गुना बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने पर जोर दे रहे हैं।

2023-24 में भारतीय कलपुर्जा उद्योग का कारोबार 6.14 लाख करोड़ रुपये (74.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था, जिसमें निर्यात का हिस्सा 21.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष के दौरान आयात 20.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

खरीदनी है सबसे सुरक्षित गाड़ी तो दोनों में से किस कूप SUV को खरीदना होगा बेहतर

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले कुछ समय में भारतीय बाजार में कम बजट वाली दो कूप एसयूवी को अलग-अलग कंपनियों की ओर से लॉन्च किया गया है। जिनमें टाटा और सिट्रॉएन शामिल हैं। दोनों ही एसयूवी का Bharat NCAP की ओर से Crash Test भी किया गया है। सुरक्षा के मामले में किस एसयूवी को खरीदने में समझदारी होगी। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में वाहन निर्माता लगातार अपनी कारों की सुरक्षा को बेहतर कर रहे हैं। जिसका फायदा हादसों के समय ग्राहकों को भी मिलता है। Bharat NCAP की ओर से हाल में ही दो Coupe SUVs का Crash Test किया गया है। सुरक्षा के मामले में दोनों एसयूवी को कितने अंक मिले हैं। किस तरह के सेफ्टी फीचर्स इनमें ऑफर किए गए हैं। दोनों की क्या कीमत है और किसे खरीदना आपके लिए ज्यादा सुरक्षित (Tata Curvv vs Citroen Basalt Comparison) होगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

टाटा की ओर से कूप एसयूवी के तौर पर कुछ समय पहले ही लॉन्च की गई Tata Curvv को Crash Test में पूरे पांच अंक हासिल हुए हैं। इस एसयूवी को व्यस्कों के साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए भी पूरी 5स्टार रेटिंग मिली है। Bharat NCAP ने 15 October को ही इसके Crash Test के नतीजों को सार्वजनिक किया है। वहीं Citroen Basalt के भी Crash Test के नतीजों को सार्वजनिक 10-11 October के बीच किया गया था। जिसमें सिट्रॉएन की कूप एसयूवी को 4स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

बच्चों की सुरक्षा के मामले में Tata Curvv को 49 में से 43.66 अंक दिए गए हैं। 18 महीने के बच्चों के मुताबिक किए गए टेस्ट में इसे फ्रंट से 8 में से 7.07 और साइड से किए गए टेस्ट के बाद चार में से पूरे चार अंक मिले हैं। जबकि तीन साल के बच्चों के मुताबिक एसयूवी को टेस्ट में फ्रंट से आठ में से 7.59 और साइड से चार में से चार अंक मिले हैं। वहीं Citroen Basalt को 49 में से 35.90 अंक दिए गए हैं। 18 महीने के बच्चों के मुताबिक किए गए टेस्ट में इसे फ्रंट से 8 में से 8 और साइड से किए गए टेस्ट के बाद चार में से पूरे चार अंक मिले हैं। जबकि तीन साल के बच्चों के मुताबिक एसयूवी को टेस्ट में फ्रंट से आठ में से 3.90 और साइड से चार में से चार अंक दिए गए हैं।

वहीं व्यस्कों की सुरक्षा के लिए एसयूवी को फ्रंटल ऑफसेट डेफोरमेबल बेरियर टेस्ट में 16 में से 14.65 अंक मिले। साइड मूवेबल डेफोरमेबल बेरियर टेस्ट में 16 में से 14.85 अंक मिले हैं। Citroen Basalt को व्यस्कों की सुरक्षा के लिए फ्रंटल ऑफसेट डेफोरमेबल बेरियर टेस्ट में 16 में से 10.19 और साइड मूवेबल डेफोरमेबल बेरियर टेस्ट में 16 में से 16 अंक मिले। दोनों ही एसयूवी ने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया।

कैसे हैं सेफ्टी फीचर्स

Tata की ओर से Curvv एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को दिया जाता है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग को दिया गया है। जबकि सेफ्टी के लिए आई-टीपीएमएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, थ्री पाइंट सीटबेल्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, 360 डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, इमोबिलाइजर, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डीसेंट कंट्रोल, ईपीबी, एबीएस, ईबीडी, Level-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। वहीं Citroen Basalt में सेफ्टी के लिए छह एयरबैग दिए गए हैं। इसके अलावा रियर पार्क असिस्ट, ईएससी, एबीएस, ईबीडी, रियर पार्किंग कैमरा, टीपीएमएस के साथ 40 अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। जबकि मारुति ग्रैंड विटारा में कंपनी की ओर से फ्रंट और कर्टेन एयरबैग, 360 डिग्री व्यू कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस, हिल होल्ड असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

एथर एनर्जी ने शुरू की तीन विकल्प उपलब्ध वाली एथर केयर सेवा योजना

परिवहन विशेष न्यूज

एथर एनर्जी ने अपने ग्राहकों के लिए एथर केयर सेवा योजनाएँ शुरू की हैं, जो समय-समय पर रखरखाव के बारे में वित्तीय स्पष्टता की आवश्यकता को संबोधित करती हैं, क्योंकि अधिक ग्राहक प्रारंभिक तीन साल की वारंटी से बाहर निकल रहे हैं। एथर केयर योजनाएँ मुफ़्त समय-समय पर रखरखाव, घिसे-पिटे पार्ट रिप्लेसमेंट पर छूट और एक्सप्रेसकेयर और पॉलिशिंग जैसी मूल्यवर्धित सेवाएँ प्रदान करती हैं।

एथर एनर्जी मे तीन विकल्प उपलब्ध हैं। पहला एथर केयर, दूसरा एथर केयर प्लस और तीसरा एथर केयर मैक्स। प्रत्येक योजना एक वर्ष या 10,000 किलोमीटर की अवधि को कवर करती है, जो भी पहले हो।

पहले एथर केयर प्लान में दो निःशुल्क आवधिक रखरखाव सत्र, साल में एक बार घिसे-पिटे भागों पर 10% की छूट और साल में एक बार घिसे-पिटे भागों को बदलने पर श्रम पर 10% की छूट शामिल है।

दूसरे एथर केयर प्लस प्लान में दो निःशुल्क आवधिक रखरखाव सत्र, एक निःशुल्क पॉलिशिंग, एक निःशुल्क धुलाई, साल में दो बार घिसे-पिटे भागों पर 10% की छूट और साल में दो बार घिसे-पिटे भागों को बदलने पर श्रम पर 15% की छूट मिलती है।

तीसरे एथर केयर मैक्स योजना में दो निःशुल्क आवधिक रखरखाव सत्र, दो निःशुल्क ब्रेक पैड प्रतिस्थापन, दो निःशुल्क धुलाई, दो निःशुल्क एक्सप्रेस केयर सेवाएं, दो निःशुल्क पॉलिशिंग, निःशुल्क बेल्ट स्नेहन, वर्ष में दो बार टूट-फूट वाले भागों पर 10% की छूट, तथा वर्ष में दो बार टूट-फूट वाले भागों के प्रतिस्थापन के लिए श्रम पर 15% की छूट प्रदान करती है।

ग्राहक 30 सितंबर, 2024 तक एथर के अधिकृत 210 सर्विस सेंटर या 230 एक्सपीरियंस सेंटर में से किसी पर भी प्लान खरीद सकते हैं। लाभ केवल उस डीलरशिप पर भुनाए जा सकते हैं जहाँ से प्लान खरीदा गया है। प्लान की कीमत ₹1,130 से लेकर ₹2,400 तक है, जो प्लान और खरीद के शहर के आधार पर ₹5,900 तक के लाभ प्रदान करते हैं। एथर केयर प्लान की शुरूआत का उद्देश्य इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के रखरखाव लागत से संबंधित चिंताओं को दूर करना है।

चार्जज़ोन ने भारत में वाणिज्यिक ईवी के लिए पेश किया बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS)

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क चार्जज़ोन ने अपनी नई बैटरी पासपोर्ट प्रणाली शुरू की है। यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बैटरी के जीवनचक्र का विस्तृत रिकॉर्ड प्रदान करता है, तथा प्रत्येक चरण पर व्यापक जानकारी एकत्र करता है।

बैटरी पासपोर्ट सिस्टम का उद्देश्य बैटरी के पूरे जीवनकाल में पारदर्शी जानकारी प्रदान करके रैखिक से वृत्ताकार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करना है। यह पारदर्शिता ईवी बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रतिभागियों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें ईवी खरीदार, निर्माता, रीसाइकिलर और आर्थिक ऑपरेटर शामिल हैं।

यह सिस्टम बैटरी के उपयोग और मूल्य को अनुकूलित करने में भी मदद करेगा। बसों और ट्रकों जैसे वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल के माध्यम से, चार्जज़ोन बैटरी की शुरुआती लागत को कवर करेगा, पूर्व-निर्धारित माइलेज के लिए स्पष्ट ऊर्जा मूल्य निर्धारण प्रदान करेगा और विश्वसनीय प्रदर्शन मीट्रिक सुनिश्चित करेगा। यह बैटरी पैक को फिर से इस्तेमाल करने और रीसाइकिल करने में भी सहायता करेगा, जिससे बैटरी की प्रमुख विशेषताओं की

वास्तविक समय की निगरानी का उपयोग किया जा सकेगा।

चार्जज़ोन के संस्थापक और सीईओ कार्तिकेय हरियाणी ने बैटरी पासपोर्ट सिस्टम की शुरुआत को भारत में ईवी उद्योग को फिर से परिभाषित करने की दिशा में एक कदम बताया। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम में एक वित्तीय तत्व शामिल है जो ईवी और बैटरी की लागत को अलग करता है, जिससे वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा मिलता है।

शुरुआती तैनाती 200KWh बैटरी क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बसों को लक्षित करेगी, साथ ही भारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक बस बाजार में चार्जिंग-एज-ए-सर्विस (CaaS) और एनर्जी एज ए सर्विस (EaaS) के लिए दीर्घकालिक समझौते स्थापित करने की योजना है। यह प्रणाली कम-ड्यूटी साइकिल अनुप्रयोगों के लिए बैटरी को फिर से उपयोग करने की सुविधा भी प्रदान करती है।

चार्जज़ोन के समूह निदेशक रवींद्र मोहन ने बताया कि औद्योगिक IoT 5.0 प्लेटफ़ॉर्म पर निर्मित यह सिस्टम सटीक, सुरक्षित और सुलभ बैटरी जानकारी सुनिश्चित करने के लिए उद्योग मानकों को पूरा करता है। इसमें डेटा सत्यापन, बैटरी भंडारण, साझाकरण और पहचान जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है, साथ ही ईवी को वाहन और बैटरी घटकों में अलग करने के लिए नियमों का अनुपालन भी किया गया है। यह समाधान संचालन को सुव्यवस्थित करने और निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं के लिए दक्षता में सुधार करने, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में योगदान देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि बैटरी स्टोरेज क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दे रही है। अनुमानों से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की मांग के कारण भारत की बैटरी स्टोरेज क्षमता 2030 तक 600 GWh तक पहुँच सकती है। अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के हिस्से के रूप में भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक लगभग 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ना है, जिससे बैटरी स्टोरेज जैसे लचीले ऊर्जा समाधानों की आवश्यकता पर बल मिलता है।

भारत में 2022 से 2030 तक लिथियम-आयन बैटरियों की संचयी क्षमता लगभग 600 GWh होने का अनुमान है, जिसमें 2030 तक पुनर्चक्रण मात्रा लगभग 128 GWh होगी। देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा और ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा भंडारण बुनियादी ढांचे में निवेश आवश्यक है।

भारतीय छात्र पाठ्यपुस्तकों की तुलना में यूट्यूब को क्यों पसंद करते हैं?

विजय गर्ग

अभिव्यक्ति के हर माध्यम की अपनी चरित्रगत विशेषता होती है। साहित्य में लेखक अदृश्य बिंबों का सृजन करता है, जबकि सिनेमा पूर्णतः दृश्य माध्यम है। इसलिए साहित्य का सिनेमा में रूपांतरण सीधे-सीधे अदृश्य का दृश्यों में रूपांतरण होता है। वह भी कला या मूर्तिकला की तरह एक स्थिर चाक्षुष बिंब भर में नहीं, बल्कि पूर्णतः जीवंत और प्रत्यक्ष नजर आते जीवन के घटनाक्रम में।

कुछ साल पहले, अधिकांश छात्र पुस्तकों को अपनी जानकारी के प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग करते थे। लेकिन अब, ऐसा लगता है कि ज्ञान का डिफ़ॉल्ट स्रोत यूट्यूब है। तो, पिछले कुछ वर्षों में क्या बदल सकता था? मैं एक किस्से से शुरुआत करता हूँ। विजय गर्ग ने हाल ही में प्रयोगशाला में एक प्रयोग करने के लिए छात्र द्वारा उपयोग किए जा रहे एक विशेष उपकरण की कार्यप्रणाली से संबंधित एक प्रश्न पूछा। छात्र ने बहुत आत्मविश्वास से एक विस्तृत उत्तर दिया जो पूरी तरह से गलत था क्योंकि यह भौतिकी के बुनियादी सिद्धांतों की अवहेलना करता था। विजय गर्ग थोड़े हैरान थे क्योंकि इस तरह का उत्तर केवल छात्र की समझ पर आधारित होने की संभावना नहीं है, बल्कि यह किसी किताब से होना चाहिए। तो, मैंने उनसे पूछा कि किस किताब में यह स्पष्टीकरण है। कुछ झिझक के बाद, उसने धीरे से कहा कि यह एक यूट्यूब वीडियो से है। बाद में पता चला कि यह कोई अलग मामला नहीं था - अधिकांश छात्र अब सीखने के लिए किताबों के बजाय यूट्यूब पर भरोसा कर रहे थे। चूँकि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि देश भर के छात्रों को सेवा प्रदान करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय में छात्रों का नमूना किसी तरह अद्वितीय है, कोई यह तर्क दे सकता है कि यह प्रवृत्ति अन्य स्थानों के छात्रों में भी पाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि यह बिल्कुल हालिया घटना है। कुछ साल पहले, अधिकांश छात्र पुस्तकों को अपनी जानकारी के प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग करते थे। लेकिन अब, ऐसा लगता है कि ज्ञान का डिफ़ॉल्ट स्रोत यूट्यूब है। तो, पिछले कुछ वर्षों में क्या बदल सकता था? मुझे नहीं लगता कि हम निश्चित रूप से इसका उत्तर जान सकते हैं लेकिन कुछ प्रशंसनीय परिकल्पनाएँ हैं जिन पर हम इस परिवर्तन को समझने की कोशिश में विचार कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी ने अधिकांश शिक्षा को ऑनलाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। जहां तक सीखने का सवाल है, यह विभिन्न कारणों से विनाशकारी था। ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए एक उपकरण तक पहुंच और आवश्यक इंटरनेट बैंडविड्थ प्रारंभिक समस्याएं थीं। इसके अलावा, प्रभावी होने के लिए, ऑनलाइन शैक्षणिक तरीकों को चाक-एंड-टॉक शिक्षण से काफी अलग होना चाहिए, और हम शिक्षक इसके लिए तैयार नहीं थे। अंततः, अधिकांश छात्र स्मार्टफोन तक पहुंच पाने में सफल रहे क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा लगभग दो वर्षों तक चली। मोबाइल फोन

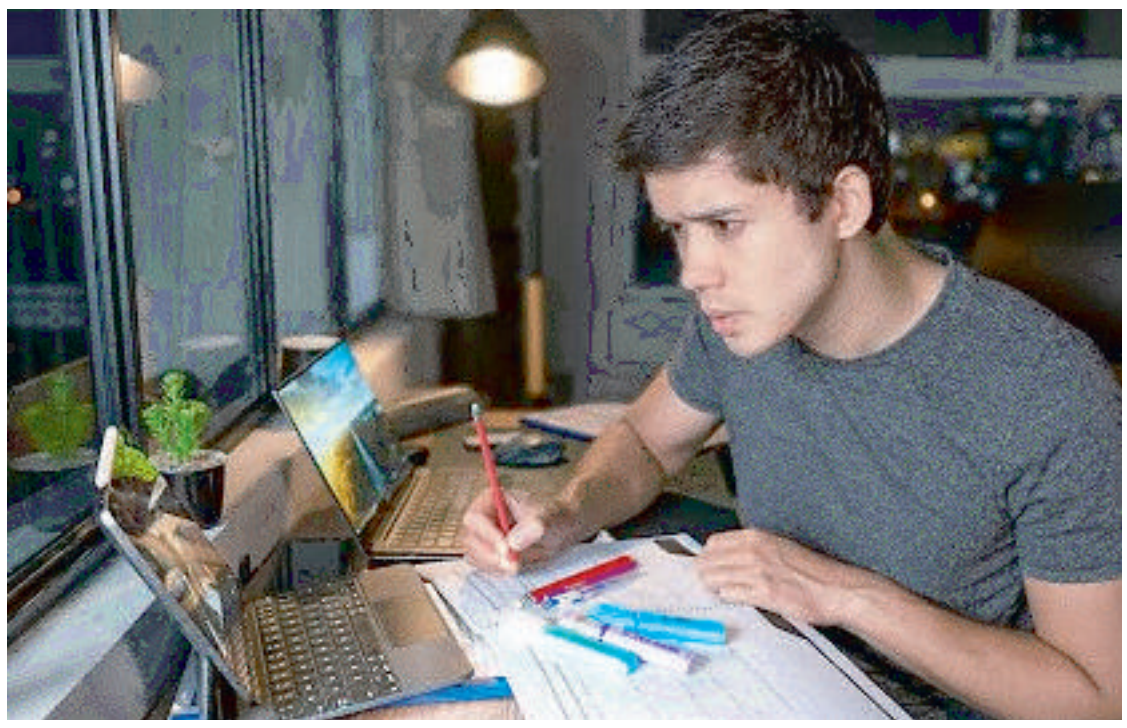

क्षेत्र में एक नए प्रवेशी के कारण डेटा की लागत में गिरावट ने भी एक भूमिका निभाई - चूंकि वीडियो को उच्च बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, किफायती डेटा ने इस संक्रमण को सुविधाजनक बनाया। यह कहानी का केवल एक हिस्सा है. हमें अभी भी यह समझने की आवश्यकता है कि छात्र अब किताबों की ओर क्यों नहीं लौटे हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण का स्थान नियमित शिक्षण ने ले लिया है। किताबों की ऊंची कीमत निश्चित रूप से इसका कारण नहीं है, क्योंकि अधिकांश छात्रों ने कुछ समय पहले किताबों की हार्ड कॉपी खरीदना बंद कर दिया था। दृढ़ सर्फर के लिए, कोई भी पुस्तक इंटरनेट पर निःशुल्क डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। हालाँकि, अपने फोन या लैपटॉप पर सॉफ्ट कॉपी से परामर्श करना भी छात्रों के बीच बहुत प्रचलित नहीं है। इसका एक कारण वर्तमान पीढ़ी के छात्रों के बड़े वर्ग के बीच दृष्टिकोण में बदलाव है। इंस्टाग्राम की यह पीढ़ी अपने समय का एक बड़ा हिस्सा अपने फोन पर रील्स देखने में बिताती है। उनका ध्यान अवधि, डिफ़ॉल्ट रूप से, कुछ मिनटों तक सीमित है। पढ़ना, अधिक से अधिक, कुछ पंक्तियों की पोस्ट तक ही सीमित है। दृश्य मीडिया के लिए इस प्राथमिकता को देखते हुए, कोई भी पूछ सकता है कि छात्र उत्कृष्ट ऑनलाइन पाठ्यक्रम क्यों नहीं ले रहे हैं, बल्कि शौकीनों द्वारा डाले गए यूट्यूब वीडियो का विकल्प चुन रहे हैं। आख़िरकार, पश्चिम में कई विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम ऑनलाइन डाल दिए हैं, और ये उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले हैं और डाउनलोड करने के लिए निःशुल्क हैं। इसके अलावा, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग (एनपीटीईएल) कुछ उत्कृष्ट पाठ्यक्रम निःशुल्क प्रदान करता है। समस्या दोहरी है. सबसे पहले, विश्वविद्यालयों और एनपीटीईएल पर दिए जाने वाले व्याख्यान आमतौर पर कई छात्रों के लिए डराने वाले होते हैं। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि ये व्याख्यान विषय की बुनियादी समझ और पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, जिसकी अधिकांश छात्रों को कमी महसूस होती है। पाठ्यक्रम भी कठोर हैं और उनके समय और ध्यान की मांग करते हैं, जिसे वे देने में अनिच्छुक हैं। भाषा का भी मुद्दा है. यह न केवल उन छात्रों के लिए सच है जिन्होंने अंग्रेजी में अपनी शिक्षा नहीं ली है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अंग्रेजी में पढ़ाया गया होगा क्योंकि कई छात्रों के लिए बोली जाने वाली अंग्रेजी की समझ चुनौतीपूर्ण है। इन छात्रों को अंग्रेजी में दिए गए ऑफ़लाइन व्याख्यान को भी पूरी तरह से समझने में कठिनाई होती है। हालाँकि, उस स्थिति में, शिक्षक आम तौर पर स्थानीय भाषा का उपयोग करके समझा सकता है ताकि कम से कम आवश्यक अवधारणा समझ में आ जाए। ऑनलाइन व्याख्यान के साथ यह कोई विकल्प नहीं है। यूट्यूब पर, आप ऐसे वीडियो पा सकते हैं, जो, यदि स्थानीय भाषा में नहीं हैं, तो आम तौर पर द्विभाषी और गैर-भयभीत तरीके से वितरित किए जाते हैं। छात्र लघु वीडियो के प्रारूप के साथ सहज महसूस करते हैं, जो उन्हें लगता है कि उन्हें विषय का सार देता है। ऐसे वीडियो की लोकप्रियता को देखते हुए, खोज एल्गोरिदम उन्हें किसी भी खोज में शीर्ष परिणामों के रूप में सामने लाता है, जो उन्हें और अधिक लोकप्रिय बनाता है, जिससे उनकी एल्गोरिदमिक रैंकिंग और भी बढ़ जाती है। मैंने वाइवा ले रहे छात्र को यह समझाने की कोशिश की कि उसे यूट्यूब पर असत्यापित सामग्री के बजाय किताबों का उपयोग क्यों करना चाहिए और उसने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी। लेकिन उसके अंदाज़ से साफ़ लग रहा था कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। निरंतर ध्यान की कमी, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और कम पढ़ने के कौशल का हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह तो समय ही बताएगा। शायद ट्विटर/इंस्टा पीढ़ी को इनकी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि चैटजीपीटी जैसे टूल पर्याप्त हो सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

संपादकीय

बिना ट्यूटर के माँ- बच्चे का जुड़ाव बढ़ाने का तरीका

सरला का बेटा चौथी कक्षा में पढ़ता है और कामकाजी मां होने के कारण हर कोई उसे यही सलाह देता है कि उसे एक ट्यूटर लगा लेना चाहिए ताकि उसका लोड कम हो और बच्चे की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया जा सकते। लेकिन सरला ने फैसला किया है कि कम से कम 10 वीं तक तो वह ट्यूटर नहीं लगाना चाहेगी जब तक कि वह खुद बच्चे के विषयों को पढ़ा सकती है।

सुबह 10 से रात 6 बजे तक ऑफिस और फिर रात 7.30 बजे से वह बच्चे को पढ़ाने बैठ जाती है। दो घंटे वह हंसते, मस्ती करते, तो कभी गंभीरता से पढ़ने-पढ़ाने में लग जाते हैं। कभी-कभी दोनों के बीच बहस और लड़ाई भी हो जाती है जिसके बारे में सोचकर सरला को बाद में हंसी भी आती है। जब पीटीएम होती है और एग्जाम में नंबर उतने मनमाफिक नहीं आते हैं, तो उस समय उसके मन में ख्याल आता है कि क्या वाकई मुझे ट्यूटर लगा लेना चाहिए। लेकिन वह सोचती है कि अगर ट्यूटर लगा लिया तो जो मोमेंट्स उस पढ़ाई के दौरान वह बेटे के साथ जी रही है, उससे वंचित हो जाएगी। वह समय दोनों के लिए बहुत ही खास है। सरला का ट्यूटर न लगाना और कामकाजी होते हुए बच्चे को खुद पढ़ाने का फैसला लेना किस तरह फायदेमंद हो सकता हैं, यहां जान लेते हैं। सरला की कहानी जानकर तो लगता है कि वह अपने बेटे के साथ क्वॉलिटी टाइम बिताते हुए अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए अच्छा काम कर रही हैं। यहां कुछ तरीके बता रहे हैं। जिनसे ट्यूटर को हायर न करना मां और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है:

आपके बच्चे के लिए फायदा पर्सनलाइज्ड अटैंशन - आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से जानते हैं और यह बखूबी समझते हैं कि किन क्षेत्रों में उसे ज्यादा मदद की ज़रूरत हैं, इससे आप अपनी टीचिंग को उसकी ज़रूरतों के अनुरूप बना सकते हैं।

भावनात्मक सुरक्षा इस तरह आप उनकी मां के साथ टीचर भी होंगी। अपनी टीचर के रूप में पाकर बच्चा ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा। आप उसके लर्निंग में शामिल हैं, यह जानकर वह सपोर्ट महसूस करेगा।

लर्निंग स्टाइल - बच्चा सबसे अच्छा कैसे सीखता है, उसके आधार पर आप पढ़ाने की गति और तरीकों को एडजस्ट कर सकती हैं। यह हमेशा किसी ट्यूटर के साथ संभव नहीं हो पाता है। जीवन के सबक - शिक्षा से परे, आप उस दौरान उसे ऐसी कई बातें सीखा सकते हैं, जो कि लाइफ स्किल्स और वैल्यूज़ से जुड़ी हों। मां के लिए फायदे मजबूत होगी बॉडिंग- यह समय आपको उनके साथ गहरे स्तर पर जुड़ने, उसकी चुनौतियों को समझने और उसकी उपलब्धियों का जश्न मानने का मौका देता है। इसे आप दोनों के बीच बॉडिंग मजबूत होगी।

आप उसकी प्रोग्रेस पर नज़र एकेडेमिक प्रोग्रेस में सीधे शामिल रहती हैं, जिससे किसी भी मुद्दे का शीघ्र समाधान करना आसान हो जाता है। क्वालिटी टाइम - आपके बिजी शेड्यूल में, एक साथ समय बिताने का यह एक अनमोल अवसर है, जो आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। संतुष्टि का एहसास - अपने बच्चे को पढ़ाने से आपको संतुष्टि का एहसास होता है और उसकी शिक्षा और विकास में आपकी भूमिका मजबूत होती है।

भविष्य पर ऐसे पड़ेगा प्रभाव आपसी विश्वास- यह दिनचर्या आपके और आपके बच्चे के बीच विश्वास और संचार की मजबूत नींव बना सकती है। बनेंगे इंडिपेंडेंट - जैसे ही आप उसे गाइड करती हैं, वह सीखता है कि समस्याओं से कैसे निपटा जाए और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे विकसित की जाए, जो उसे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। यह दृष्टिकोण न केवल उसके एकेडेमिक ग्रोथ के लिए बल्कि इमोशनल बॉन्ड के लिए भी फायदेमंद है जो रिश्ते में महत्वपूर्ण है। यदि कभी आप परेशान हों, तो ट्यूटर को चुनने के बजाए छोटे एडजस्टमेंट्स पर विचार करें, जैसे काम को छोटे-छोटे टास्क में बांटना या एक्सटेंसिव लर्निंग के लिए वीकेंड्स का इस्तेमाल करना। लेकिन कुल मिलाकर, यह रणनीति दोनों के लिए अच्छी और फायदेमंद लगती है।

विदेश में पढ़ाई कैसे करियर की संभावनाओं और रोजगार क्षमता को बदल देती है

विजय गर्ग

विदेश में पढ़ाई कैसे करियर की संभावनाओं और रोजगार क्षमता को बदल देती है आज की वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में कैरियर के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए विदेश में अध्ययन शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने से कहीं अधिक विकसित हुआ है। जैसे-जैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तेजी से मूल्यवान होते जा रहे हैं, छात्र दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता के लिए आवश्यक कौशल से बेहतर ढंग से सुसज्जित होते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन में एक गतिशील बदलाव देखा गया है, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकप्रिय अध्ययन स्थलों में। 2020-2021 शैक्षणिक वर्ष में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग 710,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मेजबानी की, जिसमें चीन और भारत अग्रणी थे। महामारी के कारण नामांकन में 15 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, संस्थान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए अधिक मजबूत रणनीतियों के साथ वापसी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, अपने प्रतिस्पर्धी अध्ययन-पश्चात कार्य अवसरों और सामर्थ्य के साथ, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए तेजी से आकर्षक बन गया है। 2023 तक, 570,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र वहां (एम्बर) पढ़ रहे थे। यूके में, शिक्षा की मांग मजबूत बनी हुई है, खासकर भारतीय छात्रों की ओर से, जिनकी संख्या 2023 में जारी किए गए 500,000 अध्ययन वीजा में से 30 प्रतिशत थी। ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट (जीआईआर) ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विदेश में अध्ययन करने से छात्रों को दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक कौशल से लैस करके करियर विकास में काफी वृद्धि होती है। रोज़गार क्षमता को बढ़ावा देना एक सर्वेक्षण के अनुसार, 75,000 वैश्विक नियोक्ताओं ने स्नातकों को रोजगार योग्य बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभव को महत्वपूर्ण माना है। सर्वेक्षण इस बात पर प्रकाश डालता है कि टीम वर्क, समस्या-समाधान और अनुकूलनशीलता जैसे कौशल नियोक्ताओं द्वारा अत्यधिक मांगे जाते हैं, लेकिन अक्सर उन स्नातकों में कमी पाई जाती है जिन्होंने विदेश में अध्ययन नहीं किया है (क्यूएस)। इसी तरह, इरास्मस इम्पैक्ट अध्ययन में पाया गया कि 92 प्रतिशत नियोक्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित अंतरसांस्कृतिक क्षमता की सराहना की, जिससे बेहतर रोजगार क्षमता प्राप्त हुई। प्रमुख कौशल विकास आईआईई की प्रोजेक्ट एटलस और ओपन डोर्स रिपोर्ट से पता चलता है कि विदेश में पढ़ाई का अनुभव 21वीं सदी के महत्वपूर्ण कौशल के विकास की ओर ले जाता है। IIE द्वारा सर्वेक्षण किए गए 60 प्रतिशत से अधिक छात्रों ने समस्या-समाधान, आत्मविश्वास, अनुकूलनशीलता और संचार जैसे कौशल में महत्वपूर्ण सुधार की सूचना

दी, जो आज के नौकरी बाजार में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हैं। विशेष रूप से, एसटीईएम स्नातकों को विदेश में अध्ययन कार्यक्रमों से लाभ हुआ है। आईआईई अध्ययन के अनुसार, अपने अध्ययन के क्षेत्र से बाहर अध्ययन करने वाले 47 प्रतिशत एसटीईएम छात्रों ने कहा कि अनुभव ने नौकरी की पेशकश में योगदान दिया, जिससे साबित होता है कि अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम अकादमिक विशेषज्ञता से परे विस्तारित होते हैं। उद्यमशीलता एवं नेतृत्व विकास विदेश में पढ़ाई का एक अनूठा लाभ उद्यमशीलता की सोच को बढ़ावा देना है। इरास्मस प्रभाव अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि इरास्मस में भाग लेने वाले दस छात्रों में से एक ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, और उनमें से 70 प्रतिशत से अधिक ने भविष्य में ऐसा करने की योजना बनाई है (ईयू बिजनेस)। जो छात्र विदेश में पढ़ते हैं, उनके अपने संगठनों में नेतृत्व की भूमिका निभाने की संभावना अधिक होती है। लिंक्डइन इकोनॉमिक ग्राफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन से भारतीय स्नातकों को उद्योगों में नेतृत्व की भूमिकाओं में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलती है। वैश्विक गतिशीलता सहभागिता न केवलक्या विदेश में अध्ययन करने से रोजगार क्षमता बढ़ती है, लेकिन यह वैश्विक गतिशीलता में शामिल होने की अधिक इच्छा को भी बढ़ावा देता है। इरास्मस प्रभाव अध्ययन से पता चलता है कि इरास्मस के पूर्व छात्रों के काम या अध्ययन के लिए देश बदलने की संभावना दोगुनी है, जो वैश्विक सेटिंग्स में उनकी अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करता है। क्यूएस ग्लोबल नियोक्ता सर्वेक्षण इंगित करता है कि नियोक्ता उन उम्मीदवारों को महत्व देते हैं जो वैश्विक भूमिकाओं के लिए खुले हैं, उन्हें अधिक बहुमुखी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार चुनौतियों से निपटने में सक्षम मानते हैं। दीर्घकालिक कैरियर लाभ विदेश में अध्ययन के लाभ तत्काल रोजगार परिणामों से कहीं अधिक हैं। इरास्मस इम्पैक्ट स्टडी इस बात पर प्रकाश डालती है कि मोबाइल छात्र, विशेष रूप से वे जो अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप या कार्य प्लेसमेंट में संलग्न हैं, अक्सर अपनी मेजबान कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव प्राप्त करते हैं। 50 प्रतिशत से अधिक मोबाइल छात्रों का मानना है कि उनके अंतरराष्ट्रीय अनुभव ने उनके करियर की संभावनाओं में काफी सुधार किया है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन से पदोन्नति जल्दी होती है, एक वर्ष के लिए विदेश में अध्ययन करने वाले 68 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि अनुभव से करियर में उन्नति हुई। सबूत स्पष्ट है: विदेश में पढ़ाई करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे-जैसे वैश्वीकरण उद्योगों में बदलाव ला रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव चाहने वाले छात्र दीर्घकालिक सफलता के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।

इंसानियत का विस्तार

विजय गर्ग

अगर हम अपनी सारी क्षमताओं और उपलब्धियों को एक तरफ रख दें, लेकिन अपनी इंसानियत को नहीं सजाएं, तो वास्तव में हमारी जीवन यात्रा अधूरी रह जाती है। किसी की परिस्थिति को समझने और उससे संबंधित होना इंसानियत की एक महत्त्वपूर्ण निशानी है। जब हम दूसरों की समस्याओं और चुनौतियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम एक संवेदनशील और सहानुभूति से भरे हुए व्यक्ति बनते हैं, बल्कि हमें यह भी अहसास होता है कि हमारी अपनी समस्या कितनी छोटी हो सकती है। दूसरों की स्थिति और अनुभवों को समझना हमें अधिक सहानुभूतिशील और करुणामय बनाता है। यह हमें न केवल बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि हमें समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा भी देता है। इंसानियत का सार वास्तव में यही है कि हम एक-दूसरे की परिस्थितियों, दुखों और खुशियों को समझें और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। हमारे विकास और हमारी उपलब्धियों से ज्यादा महत्त्वपूर्ण यह है कि हम एक इंसान के रूप में क्या हैं। यह विचारशीलता, संवेदनशीलता और एक-दूसरे के प्रति सम्मान और दया की भावना को समेटता है। जब हम अपनी इंसानियत को प्राथमिकता देते हैं, हम सच्चे मायनों में जीने लगते हैं और हमारे कार्यों में एक गहरा अर्थ आ जाता। इस दृष्टिकोण से सच्चे अमीर और सफल वही हैं जो अपने जीवन में पूर्णता और मानवता को महत्त्व देते हैं, न कि केवल बाहरी उपलब्धियों या स्वार्थ को। भावनाएं एक व्यक्ति की अंतरात्मा का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, जो हमारे अनुभवों और संबंधों को गहराई प्रदान करती हैं। उनकी सच्ची समझ के लिए हमें अपनी संवेदनशीलता को जागृत करना पड़ता है और दूसरे के अंतर्मन को जानने का प्रयास करना पड़ता है। जब हम यह कर पाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी एक गहरे स्तर पर जुड़ पाते हैं।

अक्सर हम अपनी अपेक्षाओं और इच्छाओं को पूरा न होने पर निराश हो जाते हैं, जबकि हम यह नहीं सोचते कि कितने लोग हमारे कामों, व्यवहार और हमारी क्षमताओं से उम्मीदें रखते हैं। जब हम अपनी समस्याओं और असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे पास दूसरों के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। यह समझ कि हमसे कितने लोग उम्मीद रखते हैं और उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमें अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बना सकती है। यह समझ हमें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित करती है, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। समाज में सकारात्मक बदलाव और सुधार तभी संभव है जब हम एक-दूसरे के साथ समझदारी और समर्थन के साथ पेश आते हैं। यह मान लेना कि केवल हम ही किसी खास काम को सही तरीके से कर सकते हैं, वास्तव में एक भ्रम हो सकता है। आज के समय में इतने सारे विकल्प और संसाधन उपलब्ध हैं कि बहुत सारी समस्याओं में समाधान या काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं। यह मान्यता कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, कभी-कभी आत्म-सीमा की ओर इशारा करती है। हम सभी अपनी-अपनी जगह महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि अन्य लोग भी उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, जिन्हें हम अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं। यह दृष्टिकोण हमें और अधिक खुला और सहायक बनाता है और समस्याओं को सुलझाने में नए और प्रभावी तरीकों को अपनाने में मदद करता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं और एक-दूसरे के दृष्टिकोण और भावनाओं की कद्र करते हैं, तो इससे काम की गुणवत्ता सुधार होता है और आपसी विश्वास व समझ भी बढ़ती है। सहयोग का मतलब सिर्फ साथ काम करना नहीं, बल्कि एक-दूसरे की मदद करना और विचारों का आदान-प्रदान करना भी है। जब भलाई और मदद बिना किसी स्वार्थ, लालच या अपेक्षा के की जाती है, तो इसका प्रभाव और अधिक गहरा और वास्तविक होता है। ऐसी भलाई न केवल दूसरों के दिल को छूती है, बल्कि हमें भी आत्मिक संतोष और खुशी देती है। स्वार्थ और लालच से मुक्त होकर की गई मदद में एक सहजता और ईमानदारी होती है, जो इसे और अधिक मूल्यवान बनाती है। इस तरह की भलाई से न तो किसी के प्रति अहसान जताने की जरूरत होती है और न ही किसी प्रकार की मनवाने की प्रवृत्ति होती है। यह मदद खुद में एक पुरस्कार होती है और इससे दोनों पक्षों को सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त होता है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं, तो यह दिखाता है कि

हम अपने मूल्यों और मानवता के प्रति सच्चे हैं। यह न केवल हमारे संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि हमें आत्मिक रूप भी समृद्ध बनाता है। यह हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाता है और हमारे संबंधों को मजबूत और सार्थक बनाता है।

हमारी स्थिति और हमारी अपेक्षाओं की तुलना में दूसरों की उम्मीदें भी महत्त्वपूर्ण होती हैं। जब हम दूसरों की उम्मीदों और विश्वास को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, बल्कि एक जिम्मेदार और प्रभावशाली इंसान भी बनते हैं। किसी की परिस्थिति से रूबरू होना और उसके दर्द, संघर्ष या खुशी को समझना ही इंसानियत का मूल है। जब हम दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने का प्रयास नहीं करते, तो हम अपनी इंसानियत का एक महत्त्वपूर्ण पहलू खो देते हैं। एक सच्चा इंसान होने का मतलब है कि हम अपने अनुभवों के लिए संवेदनशील हों, साथ ही दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों के प्रति भी सहानुभूतिशील रहें।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार

किसान होंगे मालामाल, मोदी सरकार ने गेहूं और चना समेत 6 फसलों पर MSP बढ़ाई

परिवहन विशेष न्यूज

आज यूनियम कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने किसानों को दिवाली से पहले ही तोहफा दे दिया। दरअसल कैबिनेट ने 6 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी का एलान किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दीवाली-छठ से पहले किसानों का ख्याल करते हुए छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में अच्छी वृद्धि की है। यह वृद्धि न्यूनतम 130 रुपये एवं अधिकतम तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल है। गेहूं के एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटलकी वृद्धि कर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सबसे ज्यादा वृद्धि रेपसीड और सरसों के दाम में हुई है। इसमें प्रति क्विंटल तीन सौ रुपये बढ़ाया गया है।

इसी तरह मसूर के दाम में 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। केंद्र के इस फैसले को झारखंड, महाराष्ट्र एवं दिल्ली में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकारी दर पर रबी फसलों की खरीद-बिक्री का सत्र अप्रैल 2025 से शुरू होगा। विशेष उल्लेखनीय यह है कि अधिकतर फसलों की एमएसपी अब लागत के लगभग डेढ़ गुना हो चुकी है जिसकी मांग होती रही थी।

कैबिनेट ने फसलों पर कितनी एमएसपी बढ़ाई

फसल	कितनी बढ़ी MSP
गेहूं	2425 रुपये प्रति क्विंटल
जौ	130 रुपये प्रति क्विंटल
चना	210 रुपये प्रति क्विंटल
मसूर	275 रुपये प्रति क्विंटल
सरसों	300 रुपये प्रति क्विंटल
कुसुंभ (Safflower)	140 रुपये प्रति क्विंटल

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार का यह फैसला किसानों के कल्याण से जुड़ा है। खरीफ की तरह रबी फसलों के एमएसपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। देश में खरीफ धान के बाद दूसरी सबसे बड़ी रबी फसलों में गेहूं है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए सरकार को प्रत्येक वर्ष लगभग चार सौ लाख टन खाद्यान्न की जरूरत पड़ती है, जिसमें धान एवं गेहूं प्रमुख फसलें हैं। खरीफ मौसम में सरकार ने धान समेत 17 फसलों के एमएसपी में वृद्धि की थी। अब रबी में गेहूं के समर्थन मूल्य को पिछले वर्ष के 2,275 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

देश में खाद्य तेलों और दालों की भारी कमी है। इसके लिए हम विदेशों से आयात पर निर्भर रहते हैं। इन दोनों खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 2027 तक लक्ष्य रखा है। तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इसके दाम में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। रैपसीड एवं सरसों के बीज का समर्थन मूल्य 300 रुपये बढ़ाकर 5,950 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

मसूर के एमएसपी को 275 रुपये बढ़ाकर 6,700 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि चने के एमएसपी में 210 रुपये बढ़ाते हुए 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

कैसे तय किया गया रबी फसलों का एमएसपी

रबी फसलों का एमएसपी 2018-19 के केंद्रीय बजट की घोषणा के अनुरूप ही तय किया गया है। लागत का आकलन उत्पादन में आने वाले संपूर्ण खर्च है। एमएसपी इससे कम-से-कम डेढ़ गुना अधिक होगा। इसी के अनुरूप लागत की तुलना में गेहूं का एमएसपी 105 प्रतिशत है।

रैपसीड और सरसों के लिए 98 प्रतिशत, दाल के लिए 89 प्रतिशत, चना के लिए 60 प्रतिशत, जौ के लिए 60 प्रतिशतऔर कुसुम के लिए 50 प्रतिशत है। लागत में सभी तरह के भुगतान की राशि शामिल होती हैं। जैसे मानव एवं मशीन श्रम, पट्टे की जमीन के लिए भुगतान किया गया किराया; बीज, उर्वरक, खाद आदि की खरीदारी में खर्च रुपये, सिंचाई शुल्क, औजारों और कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेट आदि के संचालन के लिए डीजल, बिजली, विविध खर्च और पारिवारिक श्रम का मूल्य होता है।

वैष्णव ने कहा कि एमएसपी में वृद्धि से किसानों को लाभकारी मूल्य और फसल

काबू से बाहर क्यों हो रही महंगाई, क्या अब ब्याज दरें कम नहीं करेगा RBI?

आरबीआई ने हालिया MPC मीटिंग में लगातार 10वीं बार रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। हालांकि उसके रुख में थोड़ा बदलाव नजर आया और उसने दिसंबर की मीटिंग में कटौती का संकेत भी दिया। लेकिन इसके लिए महंगाई का काबू में रहना बेहद जरूरी है। खुदरा महंगाई के हालिया आंकड़े डराने वाले हैं। ऐसे में ब्याज दरें कम होने का इंतजार काफी लंबा हो सकता है।

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने हालिया मीटिंग में संकेत दिया था कि दिसंबर में रेपो रेट यानी नीतिगत ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। इससे सस्ते होम लोन और ऑटो लोन की उम्मीदें भी बढ़ गई थीं। लेकिन, सोमवार को जारी खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब ब्याज दरें घटने का इंतजार बढ़ सकता है।

SBI रिसर्च का कहना है कि सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ने से आरबीआई लंबी अवधि तक रेपो रेट पर तटस्थ रुख अपना सकता है। अगर उसे रेपो रेट में कटौती करनी पड़ी, तो इसकी वजह भी मुद्रास्फीति ना होकर विकास दर होगी। दरअसल, रेपो रेट में कटौती न करने से इकोनॉमिक गतिविधियां सुस्त हो रही हैं। इसलिए आरबीआई के सामने महंगाई और ब्याज दरों को एकसाथ साधने की चुनौती है।

क्या कह रही SBI रिसर्च

एसबीआई रिसर्च की दलील दी है कि अगर आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव जारी रहती है, तो शीर्ष बैंक रेपो रेट कटौती के मानदंडों पर दोबारा विचार करेगा। खाद्य कीमतों में होने वाला बदलाव घरेलू मुद्रास्फीति को प्रभावित करेगा। सितंबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अगस्त के 3.65 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 5.49 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

क्यों बढ़ रही है महंगाई दर

महंगाई दर मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल से बढ़ी है। खाद्य पदार्थों में सब्जियों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और कुल मुद्रास्फीति में इसने 2.34 प्रतिशत का योगदान दिया। ग्रामीण और शहरी खाद्य मुद्रास्फीति क्रमशः 9.08 प्रतिशत और 9.56 प्रतिशत रही, जो यह दर्शाता है कि खाद्य कीमतें परिवारों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। खासकर, सब्जियों के दाम चिंता बढ़ा रहे हैं। आलू, टमाटर और प्याज के दाम लगातार ऊपर बने हुए हैं। इससे खाद्य महंगाई नीचे नहीं आ पा रही है।

गांवों में तेजी से बढ़ रही महंगाई

एसबीआई रिसर्च के मुताबिक, ग्रामीण मुद्रास्फीति में वृद्धि शहरी मुद्रास्फीति से अधिक बनी हुई है। साथ ही ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों (लगातार 7वें महीने) के बीच अंतर में वृद्धि के परिणामस्वरूप ग्रामीण घरेलू कीमतें शहरों के मुकाबले अधिक हैं। हालिया एमपीसी मीटिंग में आरबीआई ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर जस का तस रखा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि हमारा ध्यान महंगाई को काबू में लाने पर बना हुआ है।

वैश्विक संकट के बावजूद भारत का निर्यात बढ़ा; रेडीमेड गारमेंट, फार्मा सेक्टर ने दिखाया दम

परिवहन विशेष न्यूज

सितंबर में वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल सितंबर की तुलना में 10.55 प्रतिशत रेडिमेड गारमेंट्स में 17.3 प्रतिशत फार्मा में 7.22 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में 7.89 प्रतिशत तो लेदर व लेदर उत्पाद में 8.86 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। वैश्विक स्तर पर नए-नए बाजार की तलाश व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सम्मेलन में भाग लेने से भारतीय गारमेंट के निर्यात में दहाई अंक में बढ़ोतरी हुई है।

नई दिल्ली। मध्य एशिया व यूरोप में तनाव से वैश्विक व्यापार के प्रभावित होने के बावजूद सितंबर में वस्तुओं के निर्यात में 0.51 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले छह महीनों में वस्तु निर्यात में 1.02 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। इंजीनियरिंग गुड्स, रेडीमेड गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, फार्मा जैसे रोजगारपरक सेक्टर के निर्यात में बढ़ोतरी से सितंबर के कुल निर्यात में इजाफा रहा।

सितंबर में वस्तुओं का कुल निर्यात 34.5 अरब डॉलर का तो आयात 55.3 अरब डॉलर का रहा। इस वजह से सितंबर में व्यापार घाटा 20 अरब डॉलर के पार चला गया। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि भारत वस्तु व सेवा निर्यात के मामले में तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अन्य देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

उन्होंने बताया कि सेवा निर्यात को मिलाकर अप्रैल-सितंबर में देश का कुल निर्यात 393 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-सितंबर में वस्तु निर्यात 213 अरब डॉलर का रहा।

गारमेंट सेक्टर में कुशल गैर कुशल दोनों प्रकार के लोगों को रोजगार मिलता है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार अमेरिका बना हुआ है। इसके बाद यूएई, नीदरलैंड, यूके और चीन का नंबर आता है। लेकिन भारत सबसे अधिक आयात चीन से कर रहा है।

निर्यात प्रतिस्पर्धा कैसे आएगी?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को उद्योग जगत से कहा कि वह वैश्विक बाजारों का दोहन करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि निर्यात प्रतिस्पर्धा सरकारी सब्सिडी या समर्थन से नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग जगत को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की मैन्यूफैक्च¨रग के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उद्योग जगत के लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि उन्हें गुणवत्तापरक सामान बनाना चाहिए।

सरकार को शुरुआत में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों पर उद्योग से विरोध का सामना करना पड़ा था। गोयल ने कहा, 'निर्यात प्रतिस्पर्धा सब्सिडी या समर्थन से नहीं आने वाली है। यह दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए हमारे दरवाजे बंद करने से भी नहीं आने वाली है। अगर हम आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो यह तभी हो सकता है जब भारत आत्मविश्वासी होगा और यह आत्मविश्वास तभी आएगा जब हम सभी यह तय करेंगे कि गुणवत्ता हमारा काम नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है।'

उन्होंने कहा कि यदि भारतीय उद्योग किसी ऐसे उत्पाद में प्रतिस्पर्धी नहीं है, जिसे आयात किया जा सकता है, तो उद्योग को प्रतिस्पर्धा की दिशा में काम करना होगा जहां उसे अन्य देशों के साथ तुलनात्मक लाभ हो। गोयल ने कहा, 'भारत को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं का मैन्यूफैक्चरर बनने की आकांक्षा रखनी होगी और इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलनी चाहिए।'

औषधि उद्योग का उदाहरण देते हुए मंत्री ने बड़े उद्योगपतियों से इस क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों का सहयोग करने को कहा। मंत्री ने उद्योग से बीआइएस (भारतीय मानक ब्यूरो) समितियों में हिस्सा लेने का भी आग्रह किया।

सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड, चांदी में भी तेजी; जानें दोनों का लेटेस्ट प्राइस

परिवहन विशेष न्यूज

सोने की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। इसकी कई वजहें हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और पश्चिम एशिया में अशांति से अस्थिरता सबसे अहम है। साथ ही इक्विटी मार्केट में गिरावट ने भी सोने के भाव को हवा दी है। अगर अमेरिका का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में आक्रामक कटौती जारी रखता है तो ब्याज दरों में और भी ज्यादा उछाल आएगा।

नई दिल्ली। सोने की कीमतों में लगातार उछाल जारी है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, आभूषण विक्रेताओं की खरीदारी के कारण बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 250 रुपये बढ़कर 78,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। यह गोल्ड का नया ऑल टाइम हाई है। पिछले कारोबारी सत्र में यह कीमती धातु 78,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

चांदी के भाव में उछाल देखा गया। सिक्का निर्माताओं के साथ औद्योगिक मांग बढ़ने से चांदी का रेट 1,000 रुपये बढ़कर 93,500 रुपये प्रति किलो हो गया। मंगलवार को चांदी 92,500 रुपये प्रति किलो के पर बंद हुई थी। वहीं, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 250 रुपये बढ़कर 78,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि इसका पिछला बंद भाव 78,250 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

सोने का क्यों बढ़ रहा भाव?

ट्रेडर्स का कहना है कि स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की ओर से सोने की मजबूत डिमांड दिख रही है। इसकी वजह शादियों के साथ फेस्टिव सीजन भी है। साथ ही, इक्विटी बाजारों में गिरावट भी आई है, जिससे निवेशक सोने का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इसे सबसे सुरक्षित निवेश समझा जाता है।

एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा, ₹एमसीएक्स में बढ़त के साथ सोने की कीमतें ऊंची रहीं, जबकि कॉमेक्स गोल्ड 2,675 डॉलर से ऊपर कारोबार कर रहा था। ट्रेडर्स को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती के अपने रास्ते पर कायम रहेगा।₹

त्रिवेदी का कहना है कि इससे सोने की कीमतों में उछाल आने का अनुमान है, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती से निवेशक सोने का रुख करने लगते हैं। सितंबर में सोना रिकॉर्ड उंचाई पर पहुंचने से बाद थोड़ा स्थिर हो गया था, क्योंकि ट्रेडर्स का मानना था कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती की रफ्तार सुस्त कर सकता है।

जल्दबाजी नहीं कर रहे ट्रेडर्स

हालांकि, फिर भी ट्रेडर्स ने थोड़ा सतर्क रुख जरूर अपना रखा है। मोदीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में कमोडिटी रिसर्च के वरिष्ठ विश्लेषक मानव मोदी ने कहा, ₹अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की मिली-जुली टिप्पणियों ने ट्रेडर्स को चिंतित कर रखा है। गवर्नर क्रिस्टोफर वालर ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लचीलेपन के हालिया संकेतों और स्थिर मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए कहा कि वे आने वाले महीनों में दरों को और कम करने के प्रति सतर्क रुख का समर्थन करते हैं।₹

फेड के अधिकारी इस बात पर बंटे हुए हैं कि साल के अंत तक ब्याज दरों में कितनी कटौती की जाएगी। अमेरिकी फेड नीति में और ढील देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बाजार केंद्रीय बैंक से आने वाले आर्थिक आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि ब्याज दरों में कटौती की दिशा के बारे में स्पष्ट तस्वीर मिल सके। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के निकट आने से जुड़ी अनिश्चितता और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों से सोने की मजबूती को समर्थन मिल रहा है।

मोतीलाल ओसवाल के मोदी ने कहा कि इस सप्ताह फोकस अमेरिकी खुदरा बिक्री, औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) और चीन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आंकड़ों पर रहेगा, जो निकट भविष्य में सर्राफा कीमतों की दिशा के बारे में जानकारी देंगे।

पेंशनभोगियों की शिकायत चुटकियों में होगी हल, सरकार ने सभी विभागों को दे दिया आदेश

पेंशनभोगियों की शिकायतों का अक्सर समय पर निपटारा नहीं हो पाता। अब सरकार ने आदेश दिया है कि पेंशनभोगियों की शिकायत का 21 दिन के भीतर निपटारा चाहिए। किसी भी मामले में शिकायत को यह कहकर भी बंद नहीं किया जाएगा कि यह इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। साथ ही सरकार ने डीए बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की दिवाली की सौगात भी दी है।

नई दिल्ली। केंद्र ने अपने सभी मंत्रालयों/विभागों से पेंशनभोगियों की शिकायतों का 21 दिनों के भीतर निपटारा करने को कहा है। साथ ही कहा है कि जिन मामलों में शिकायतों के निवारण में अधिक समय लगता है, वहां अंतरिम जवाब दिया जा सकता है।

दिशानिर्देश के अनुसार, अगर कोई पेंशनभोगी अपनी पेंशन कम या न आने की शिकायत करता है और संबंधित विभाग उसकी कंप्लेन को क्लोज कर देता है, तो शिकायतकर्ता 30 दिन के भीतर उसके खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है। यह अपीलीय प्राधिकारी उसकी कंप्लेन का 30 दिन के भीतर निपटारा करेंगे।

केंद्र सरकार ने अपने पेंशनभोगियों की शिकायत निवारण प्रणाली यानी केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस) पोर्टल की समीक्षा के बाद व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि दिशानिर्देशों में शिकायतों के शीघ्र और कुशल निवारण की परिकल्पना की गई है।

शिकायत टाल नहीं सकेंगे सरकारी विभाग

केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायतों से निपटने के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों में से एक में कहा गया है कि मंत्रालयों/विभागों को पेंशनभोगियों की शिकायतों का तीन सप्ताह के भीतर निपटारा करने का प्रयास करना चाहिए। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि किसी भी मामले में शिकायत को यह कहकर बंद नहीं किया जाएगा कि यह इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

इसमें कहा गया है कि शिकायत को उसके निर्णायक निवारण के बिना बंद नहीं किया जाएगा और शिकायत को बंद करते समय कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को सहायक सूचना और दस्तावेज के साथ भरा जाना चाहिए।

मंत्रालय/विभाग पोर्टल पर लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों की मासिक समीक्षा करेंगे ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। इसमें कहा गया है कि नोडल लोक शिकायत अधिकारियों को शिकायतों की प्रवृत्ति और शिकायतों के मामले की जांच के लिए मूल कारण का विश्लेषण करने के लिए कहा गया है।

सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगियों को दिवाली गिफ्ट

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली की सौगात भी दी है। सरकार ने बुधवार को महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया।

महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी इस साल जुलाई से लागू मानी जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन के साथ उन्हें तीन महीने का महंगाई भत्ता एरियर के रूप में मिल जाएगा। सरकार के इस फैसले से 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारी तो 64.89 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। लेकिन खजाने पर सालाना 9,448.35 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।

अमूमन सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा करती है जो जनवरी और जुलाई से मान्य होती है। इससे पहले गत मार्च में महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। खुदरा महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए सरकार महंगाई भत्ते को बढ़ाती है।

पर्यावरण पाठशाला: अपनी सोसाइटी और समुदाय के लिए ग्रीन बडी बनें

आज के समय में जब हर कोई तकनीकी विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है, हम कहीं न कहीं प्रकृति और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। भविष्य में हमारे पास सब कुछ होगा – अच्छे घर, शानदार गाड़ियाँ, उच्च तकनीक वाले उपकरण – लेकिन एक चीज़ जो शायद हमारे पास नहीं होगी, वह है अच्छा स्वास्थ्य। इसलिए हमें आज ही से शुरुआत करनी होगी, अपनी सोसाइटी और समुदाय के लिए एक ग्रीन बडी बनकर।

ग्रीन बडी बनने का अर्थ

एक ग्रीन बडी बनने का मतलब है, अपने पर्यावरण को साफ, स्वस्थ और हरित बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी लेना। यह केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए ताकि हम एक मजबूत और प्रकृति-हितैषी समाज बना सकें।

कदम-कदम पर बदलाव लाएं

पौधारोपण करें: अपनी सोसाइटी के हर खाली स्थान पर छोटे-छोटे पौधे लगाएँ। इसे एक नियमित अभ्यास बनाएं और बच्चों को भी शामिल करें ताकि उन्हें प्रकृति की अहमियत समझ में आए।

अपशिष्ट प्रबंधन: कचरे को सही ढंग से अलग करने की आदत डालें – सूखा कचरा और गीला कचरा। इसे अपने घर, सोसाइटी और समुदाय में लागू करें। बायोडिग्रेडेबल कचरे से कंपोस्ट बनाकर गार्डनिंग में इस्तेमाल करें।

प्लास्टिक का उपयोग कम करें: प्लास्टिक से बने सामानों का कम से कम उपयोग करें। अपने परिवार और मित्रों को भी प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित करें और बायोडिग्रेडेबल बैग और उत्पादों को प्राथमिकता दें।

जल संरक्षण: पानी का सही उपयोग और संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अपने घर की नलियों को सही रखें और पानी की बर्बादी रोकें। वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें।

ऊर्जा संरक्षण: बिजली के बिना काम करने वाले उपकरणों का अधिकतम उपयोग करें। सौर ऊर्जा को अपनाएं और अपनी सोसाइटी में इसके लिए जागरूकता फैलाएं।

पक्षियों के लिए घर बनाएं: पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करें और पेड़-पौधे लगाएं ताकि उन्हें प्राकृतिक आवास मिले। इसके अलावा, पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए भी जागरूकता बढ़ाएं।

सामूहिक प्रयास का महत्व

यदि हम केवल अपनी जिम्मेदारी निभाएँगे तो हम अपने आस-पास ही बदलाव ला सकते हैं, लेकिन अगर पूरा समाज और समुदाय एक साथ प्रयास करेगा, तो हम एक मजबूत और हरित समुदाय बना सकते हैं। हर एक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है।

बच्चों को शामिल करें

बच्चों को बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण का महत्व सिखाएं। उनके लिए ग्रीन बडी बनने की गतिविधियाँ आयोजित करें, जैसे पौधारोपण, कचरा प्रबंधन, और प्रकृति की सैर। इससे वे छोटी उम्र से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक बनेंगे और बड़े होने पर इसे जीवनशैली का हिस्सा बनाएंगे।

आज से ही एक ग्रीन बडी बनकर अपनी सोसाइटी और समुदाय में बदलाव लाएँ। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ और हरा-भरा पर्यावरण देना है। हमें यह समझना होगा कि भविष्य में भले ही हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन अगर हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य और साफ-सुथरी प्रकृति नहीं होगी, तो वह सब कुछ बेकार हो जाएगा।

आइए, पर्यावरण पाठशाला के साथ मिलकर एक ग्रीन बडी बनें और अपनी सोसाइटी को एक मजबूत और प्रकृति-हितैषी स्थान बनाएं।

indiangreenbuddy@gmail.com

पानी की समस्या को लेकर डीएम ऑफिस के बाहर किया गया प्रदर्शन

नईदिल्ली। राजधानी दिल्ली में आज पानी की समस्या एक बात बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी की समस्या से जूझते दिखाई दे रहे हैं। पानी की इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में बुधवार को स्थानीय लोगों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला. पानी की समस्या को लेकर कापसहेड़ा गांव के लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली जल बोर्ड की खराब नीतियों को लेकर किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। प्रदर्शन के माध्यम से लोगों ने सरकार के समक्ष अपनी बातें रखी और पानी की समस्या के समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि क्षेत्र में पानी की समस्या विगत कई वर्षों से चल रही है। इस समस्या को लेकर लोगों ने शासन और प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं निकाला जा सका। शासन और प्रशासन के इसी ढुलमुल रवैए से परेशान बुधवार को बड़ी संख्या में लोगों ने अपना आक्रोश दिखाते हुए यह विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्य लोगों में राय सिंह, तुला राम, सुभाष, जगदीश यादव, एमना कुमार, आरडब्लूए प्रधान अशोक यादव, गजराज यादव, राजकुमार यादव, सुबोध यादव, कपिल यादव और अनिल पप्पल जी शामिल थे।

सामाजिक बदलाव के लिए सेवकआर्मी डॉट कॉम शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली। महात्मा गाँधी की जयंती के अवसर पर सेवकआर्मी डॉट कॉम का शुभारंभ अहिंसा योग और मेडिटेशन सेंटर (दिल्ली) में आचार्य डॉ. लोकेश मुनि जी के करकमलों द्वारा किया गया। जैनम जैन (12 साल) और जीविका जैन (10) दवारा विकसित यह प्लेटफार्म स्वयंसेवकों और एनजीओ को जोड़ने वाली एक क्रांतिकारी डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सेवा और परिवर्तन को प्रेरित करना है।

यह प्लेटफार्म

(info@SevakArmy.com) जैनम जीविका फाउंडेशन के तहत शुरू किया गया, जिससे सामाजिक कल्याण में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। जैनम जैन ने बताया कि हमारा लक्ष्य 2 अक्टूबर 2025 तक 1 लाख स्वयंसेवकों को पंजीकृत करना है, जिसमें प्रत्येक स्वयंसेवक कम से कम 20 घंटे का योगदान देगा। गाँधी जी के सिद्धांतों अनुसार अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारी लें, तो असाधारण परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

जीविका जैन ने बताया कि यह यात्रा 2020 में एक धार्मिक पुस्तक पढ़ने की व्यक्तिगत चुनौती से शुरू हुई। 2022 में उन्होंने और जैनम ने मिलकर 50 दिनों में 50 जीवन-कौशल पुस्तकें पढ़ने का निर्णय लिया, जिससे यह मिशन अभियान के रूप में भारत में आगे बढ़ा। उन्होंने 120 से अधिक कार्यक्रम किए और 50 हजार लोगों तक पहुँचे।

आपके अनुसार इसकी मुख्य विशेषताओं में स्वयंसेवक पंजीकरण में स्वयंसेवक प्रोफाइल बना सकते हैं और रुचि अनुसार कार्य चुन सकते हैं। इसमें एनजीओ लिस्टिंग और कॉर्पोरेट सीएसआर सहित शैक्षिक भागीदारी आदि की सुविधा है।

डॉ. मुनि ने जैनम और जीविका के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह दिखाता है कि कैसे सबसे छोटे नागरिक भी सामाजिक सुधार में नेतृत्व कर सकते हैं।

झारखंड में चुनाव घोषणा के साथ ओड़िया उपेक्षा मुद्दा सक्रिय

*1948 से प्रभू जगन्नाथ,पावर हाउस की घोर उपेक्षा *

कार्तिक कुमार परिच्छा

सरायकेला, झारखंड में ओडिया सर्वाधिक उपेक्षित हैं। सर्वविदित है कि झारखंड का सबसे बड़ी चुनावी मुद्दा ओड़िया रहता है, वे यहां सरकारी रिकार्ड अल्पसंख्यक हैं । 1952के प्रथम आम चुनाव से ही हर चुनाव पूर्व इन्हें लुभावने सपने दिखाए जाते हैं । कभी ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी झारखंड में ओड़िया को रिझाने आते हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सिंहभूम में ओडिया भाषा में भाषण देती ।

पर जिस सरायकेला, खरसावां समेत तीनों सिंहभूम जिले के 14 सीटों मे से लगभग 10-11 सीटों में ओडिया मुल निवासी रहे हैं क्या वे दो जून की भी रोटी ढंग से पाते हैं यह एक यक्ष प्रश्न है ? यह बड़ा सवाल है आज झारखंड एवं ओड़िशा सरकार के समक्ष है जो भाषाई ,विकास, शिक्षा के नाम वोट मांग रहे हैं ।पर आज लगातार उपेक्षा के कारण ओड़िया लोगों की धार्मिक, ऐतिहासिक, भाषा संस्कृति यहां पुरी तरह चरमरा गयी है । ओड़िया का यह बड़ा सवाल आज सनसनी फैला दी है राजनीतिक दलों के लिए जो आने वाले समय में द्वार द्वार पर पहुंचेंगे वोट के लिए फिर साढ़े चार साल ऐसे गायब होगें जैसे सियास के सर से सिंग । अब उधर ओडिया मंच की तरफ से हर ओडिया परिवार को किसी भी पार्टी के नेताओं के चिकनी चुपड़ी बातों में न आकर अपनी विवेक का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है । ओड़िया मंच ने अपील कर कहा है कि आजतक बिहार व झारखंड अड़िया हित में कितने पैसे कहां दिए और क्या काम किये है लोगों को भली भांति परिचित होना चाहिए ।उ वोट मांग रहे लोगों से यह सवाल हर ओडिया अवश्य पुछें । किसी भी प्रकार का प्रलोभन में न आये ।

सरायकेला समेत सिंहभूम में मतदान प्रथम चरण में, 13 नवम्बर को

कार्तिक कुमार परिच्छा

सरायकेला , झारखंड का 22 वां जिला स्थित के सरायकेला, खरसावां (एस टी) एवं इचागढ़ (सामान्य) तीनों विधानसभा में 13 नवंबर को मतदान होगी। इसके साथ सिंहभूम के चाईबासा, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, मझगांव, इचागढ़ विधानसभा सीट के लिए मतदान की जायेगी ।साथ ही पूर्वी सिंहभूम में बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी में इसी दिन वोट डाले जायेंगे

जहां तक इस समय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को लेकर सबसे होट सीट बना सरायकेला की बात की जाय तो यहां मतदान को लेकर सभी प्रकार की प्रक्रिया पुरा करने में में प्रशासन जूट चुका है । उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने मंगलवार की शाम समाहरणालय के एनआईसी कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उपायुक्त ने कहा कि जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए 18 अक्टूबर को नामांकन प्रारंभ होगी तथा 25 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्कूटनी होगी तथा 30 अक्टूबर को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे जबकि मतगणना तिथि 23 नवंबर को काशी साहू महाविद्यालय में किया जाएगा। उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने कहां की भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 24 घंटे के अंदर सभी सरकारी कार्यालय एवं सरकारी क्षेत्र से राजनीतिक पार्टी के होर्डिंग एवं पोस्टर हटा लिए जा रहे हैं जबकि प्राइवेट सेक्टर मे लगे विभिन्न राजनीतिक दलों के होर्डिंग एवं पोस्टर को हटाने के लिए 72 घंटा का समय दिया गया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने चुनाव से संबंधित तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न के लिए सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है।

तीनों विधानसभा में मतदान केदो की संख्या 1050 है ,इसमें सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में कुल 431 मतदान केंद्र खरसावां विधानसभा क्षेत्र में 282 मतदान केंद्र एवं ईचागढ़ विधानसभा में 340 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

ओड़िया मंच की तरफ से अपील करते हुए भाषा , संस्कृति , ऐतिहासिक , आर्थिक शैक्षणिक विकास के संरक्षक ने कहा है इस ओड़िया मुहिम में हर एक ओडिया योद्धा हैं तथा लोकतांत्रिक तरीके से नेताओं की नेतागिरी का पोल खोलने की बात अपील की जा रही है ।

1948 से आजतक ओड़िया लोगों के उत्थान को वे भली भाती जान लें जो सिंहभूम 1936 के पहले किस षड्यंत्र से बिहार फिर 1948 में ओडिशा का एक राजस्व जिला सरायकेला को बिहार में लाया गया । सरायकेला खरसावां दो रियासत के मार्जर एग्रीमेंट के निर्देश के आलोक मे आज तक क्या हुआ कितना ओड़िया लोगों का उत्थान हुआ है ,उसमे वर्णित विकास हेतु वायदे के अनुसार।

यह राजनीतिक कारण ही है कि आज तक सरायकेला जगन्नाथ मंदिर में बिहार व झारखंड सरकारें एक कोटरा भोग तक नहीं चढ़ा पाई 1948 से ओडिया के आराध्य देवता को । जब ओडिया लोगों के देवता ही भूखे ,ठगे जाते हो तो जनता का क्या हस्र हुआ है सब जानते हैं । यह घोर निंदनीय विषय है राष्ट्रीय , अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंडी ओड़िया लोगों के लिए ।

सरायकेला ऐतिहासिक पावर हाउस आज लावारिस हो चुका है यहां गार्ड रिटायर्ड होने के बाद बिजली विभाग ने इसे लावारिस छोड़ दिया है , लाखों की मशीनें चोरी हो रही है । यह आज टूटने टूट चुका है । यहां उत्पादित बिजली से कभी सेमेमा देखने आज से सैकड़ों वर्ष पहले जमशेदपुर से लोग आते थे ।

रही बात भाषा संस्कृति की ओडिशा से मुख्यमंत्री मोहन मांझी आकर कहते हैं कि सैकड़ों ओडिया स्कुल बंद हो गये सिंहभूम में तो झारखंड के नेता सरकारें क्या कर रही थी या मोहन मांझी तथा पूर्व के मुख्यमंत्री क्या किये है 1948 से सरायकेला खरसावां, सिंहभूम ओड़िया लोगों को लिए ? मंच ने कहा है. कभी 500 से अधिक ओड़िया विद्यालय सिहभूम में था सन 1980 में भी 350 के क़रीब ओडिया स्कुल थे वे गये कहां ? । सरायकेला खरसावां आपका था मोहन बाबू आज क्यो चुप है आप ?? नवीन बाबू ने नहीं मांगे कारण वे ओडिया बोल नहीं पाते थे शायद , आप मांगिए हम साथ हैं आपके । झारखंड के ओडिया मंच ने कहा है जो नेता ओडिया लोगों का वोट मांगने आते हैं उन्हें पुछिए किस बात का बोट मांग रहे हो ? वे भी पार्टी के क्यों न हों सबसे यही संभाल दोहराई जाय ।

मुख्यमंत्री मोहन माझी ने सामान्य विमान से यात्रा की

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर : मुख्यमंत्री मोहन माझी ने सामान्य विमान से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने विशेष विमान में यात्रा करने के बजाय अपनी पत्नी के साथ साधारण विमान में यात्रा की हालाँकि, मुख्यमंत्री के 4 दिवसीय हरियाणा दौरे के लिए एक विशेष उड़ान की व्यवस्था की गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने विशेष विमान से यात्रा करने के बजाय आम यात्रियों की तरह सामान्य विमान से यात्रा की। सबसे पहले मुख्यमंत्री के दौरे के लिए विशेष विमान बुक किया गया. जिसका प्रतिदिन किराया 91 लाख 22 हजार रुपए था। इसी तरह मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए एक और विशेष विमान फाल्कन-200 पर विचार किया गया। जिसका किराया 78 लाख 55 हजार रुपये था. चूँकि दोनों विशेष उड़ानों का किराया बहुत अधिक है, इसलिए मुख्यमंत्री ने सरकारी धन बचाने के लिए सार्वजनिक धन के अनावश्यक व्यय के बिना नियमित उड़ानों से जाने का निर्णय लिया।

एक्सपो बाजार और TICA ने इंडिया एक्सपो मार्ट में भारत का पहला B2B कैश एंड कैरी वेंचर लॉन्च किया

सुषमा रानी

ग्रेटर नोएडा, भारत – 16 अक्टूबर – एक्सपो बाजार, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा की सहायक कंपनी जो होम, लाइफस्टाइल और फैशन उत्पादों के लिए एक प्रमुख मार्केटप्लेस है, ने TICA के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ भारत के पहले B2B कैश एंड कैरी वेंचर के लॉन्च की घोषणा की है। TICA यूरोप का अग्रणी B2B लाइफस्टाइल पर्चेजिंग और कैश एंड कैरी प्लेटफॉर्म है। इस पहल का उद्घाटन मुख्य अतिथि, सुरेश खन्ना, माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश, द्वारा किया जाएगा, और माननीय विशिष्ट अतिथियों, श्मर्टिजन क्लिट्यूर, प्रबंध निदेशक, TICA; दिलीप बैद, अध्यक्ष, EPCH; और रोज़ियर विवेल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, TICA, की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होगा। यह नई पहल व्यवसायियों को होम, लाइफस्टाइल और वेलनेस सेक्टर्स में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों तक अद्वितीय पहुंच प्रदान करेगी साथ ही भारत में एक गतिशील, वन-स्टॉप मार्केटप्लेस तैयार करेगी।

यह नया कैश एंड कैरी वेंचर, इंडिया एक्सपो मार्ट में स्थित है, जो पिछले दो दशकों से हैंडीक्राफ्ट्स के निर्यात का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है और प्रतिष्ठित IHGF दिल्ली मेले का आयोजन स्थल है। यह खुदरा विक्रेताओं, इंटीरियर डिजाइनरों, निर्यातकों और कॉर्पोरेट खरीदारों को थोक लेनदेन में सहजता से शामिल होने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। एक्सपो बाजार अपने विक्रेताओं की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने और B2B सहयोग के लिए एक जीवंत मार्केटप्लेस बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है।

TICA के बारे में: TICA, होम, गिफ्ट, गार्डन और फैशन क्षेत्रों में अग्रणी कंपनी है जो कि यूरोप में आपूर्तिकर्ताओं और रिसेलर्स आपस में को जोड़ता है। साथ ही यह एक

प्रेरणादायक और कुशल कंपनी है जिसके माध्यम छोटे उद्यमियों से लेकर बड़ी कंपनियों तक, बिना थोक ऑर्डर की बाध्यता के, विविध और बेहतरीन उत्पादों की खरीद की सुविधा प्रदान की जाती है। TICA ने सक्रिय उद्यमिता और सशक्त साझेदारी के जरिये अपनी जड़ों को मज़बूत किया हैं, और इसने यूरोप में B2B थोक बाजार के लिए मानक स्थापित किए हैं।

भारत के बढ़ते रिटेल सेक्टर में B2B थोक कारोबार में क्रांतिः भारत का रिटेल सेक्टर, जो राष्ट्रीय GDP में 10% से अधिक का योगदान देता है और जिसमें 2025 तक 60 नए शॉपिंग मॉल खुलने की उम्मीद है, थोक बाज़ार की बढ़ती मांग का सामना कर रहा है। एक्सपो बाजार का कैश एंड कैरी मॉडल इस मांग को पूरा करता है, जो तत्काल खरीदारी, माल की निकासी, भंडारण लागत में कमी और व्यापक विपणन में सहयोग एवं समर्थन प्रदान करता है।

IEML और एक्सपो बाजार के चेयरमैन राकेश कुमार ने इस परियोजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "एक्सपो बाजार को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के साथ व्यवसायों को सशक्त बनाने में खुशी हो रही है, जो विकास और सुविधा को बढ़ावा देते हैं। यह कैश एंड कैरी मॉडल भारत के B2B रिटेल परिदृश्य के लिए एक गेम चेंजर है, जो व्यवसायों को अनूठे उत्पादों तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है।"

TICA के मालिक मार्टिज़न क्लिट्यूर ने एक्सपो बाजार के नॉलेज पार्टनर के रूप में अपने सहयोग पर उत्साह व्यक्त किया और कहा कि "TICA को इस रोमांचक परियोजना में एक्सपो बाजार का नॉलेज पार्टनर बनने पर गर्व है। हमें विश्वास है कि यह कैश एंड कैरी परियोजना भारत में B2B और थोक बाज़ार के अनुभव को पुनर्परिभाषित करेगी। यह पहल TICA की विशेषज्ञता और एक्सपो बाजार के स्थानीय बाजार की गहरी समझ को एक साथ लाई है। यह साझेदारी आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों को विकास और सफलता का अद्वितीय अवसर प्रदान करने के लिए तत्पर है।"

कैश एंड कैरी कार्यक्रम की अनूठी विशेषताएं:

x प्रमुख स्थानः इंडिया एक्सपो मार्ट, हैंडीक्राफ्ट्स निर्यात के एक महत्वपूर्ण केंद्र में स्थित, जो अधिकतम दृश्यता और लोगों की आमद सुनिश्चित करता है।

x तत्काल बिक्रीः कैश एंड कैरी फॉर्मेट तत्काल खरीद और माल की निकासी की अनुमति देता है, भंडारण लागत को कम करता है और नकद के प्रवाह को बढ़ाता है।

x व्यापक विपणन समर्थनः लक्षित खरीदारों को आकर्षित करने के लिए व्यापक विपणन अभियानों और ब्रांड दृश्यता का लाभ देता है।

x सुगम संचालनः अत्याधुनिक डिस्प्ले सेंटर्स त्वरित और कुशल ऑर्डर प्रोसेसिंग और डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं।

x नेटवर्किंग के अवसरः प्रमुख विक्रेताओं और खरीदारों से जुड़ने, सहयोग और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने में योगदान देता है।

लक्ष्य खरीदारः

यह कार्यक्रम पेशेवर खरीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करता है, जिसमें शामिल हैं:

x रिटेलर्सः बुटीक मालिक, चेन स्टोर और डिपार्टमेंट स्टोर, जो अनूठे और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की तलाश कर रहे हैं।

x इंटीरियर डिजाइनरः पेशेवर जो अपनी परियोजनाओं के लिए अनन्य होम डेकोर और लाइफस्टाइल उत्पादों की तलाश कर रहे हैं।

x निर्यातकः व्यवसाय जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए प्रामाणिक भारतीय हस्तशिल्प का स्रोत हैं।

x थोक व्यापारीः कंपनियां जो खुदरा आउटलेट्स के लिए वितरण के लिए थोक में खरीदारी करती हैं।

x कॉर्पोरेट खरीदारः संगठन जो प्रीमियम उपहार और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए आवश्यकतानुसार उत्पादों की आवश्यकता रखते हैं।

यह ऐतिहासिक साझेदारी, जिसमें TICA एक नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल है, भारत के पहले B2B कैश एंड कैरी वेंचर को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है, जिससे व्यवसायियों के लिए बेहतरीन उत्पादों की सोर्सिंग पहले से कहीं अधिक आसान और कुशल हो जाएगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023